● वर्ष-3
● अंक-303
रायपुर, गुरुवार
01 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› पढ़ाई के साथ-साथ काम करना...

70 लाख बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा आज मिलेगा

महतारी वंदन योजना की 6 वीं किश्त में महिलाओं को मिलेगी एक-एक हजार रूपए की राशि

3061 महिला स्व-सहायता समूहों को वितरित करेंगे 100 करोड़ का ऋण

बस्तर जिले को 9.31 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जगदलपुर प्रवास के दौरान 01 अगस्त को वहां आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000-1000 रूपए की 6 वीं किश्त जारी कर राखी त्यौहार का उपहार देंगे। इस मौके पर वे महतारी वंदन एप का भी शुभारंभ करेंगे।

गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर माह एक-एक हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय 3061 महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय समावेशन के तहत 100 करोड़ का बैंक लोन का भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में शहीद गुण्डाधूर की प्रतिमा के माल्यार्पण के साथ ही नारी शक्ति से जल शक्ति रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे।

एक पेड़ माँ के नाम- मुख्यमंत्री श्री साय एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर महतारी वंदन योजना के हितग्राही के साथ ही उद्योग विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभाग के हितग्राहियों को भी सामग्री वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम का वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों के रोपण का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण एंव वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 95 लाख 85 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है।

महतारी वंदन एप का शुभारंभ

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाईल ऐप का भी शुभारंभ किया जा रहा है। इस एप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और यह राशि किस खाते में प्राप्त हुई है की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। महतारी वंदन योजना के किसी हितग्राही की असामायिक मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना भी इसी मोबाईल ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। इस एप के जरिए शिकायतें भेजी जा सकती है तथा निराकरण की स्थिति भी देखी जा सकती है। यदि किसी हितग्राही को उसे प्राप्त हो रहे लाभ त्याग करना हो तो भी मोबाईल ऐप के माध्यम से लाभ त्याग कर सकेगी। इसके अलावा शासन द्वारा योजनांतर्गत समय-समय जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की सूचना भी इसी मोबाईल ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेंगी। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की सुविधा के लिए बनाया गया यह मोबाईल ऐप एन्ड्रायड बेस है तथा इसे प्लेस्टोर से https://play.google.com/store/ apps/details/id%w®com-mahtarivandanyojan डाउनलोड किया जा सकता है।

विकास कार्यो का लोकार्पण

मुख्यमंत्री साय जगदलपुर में 9 करोड़ 31 लाख से अधिक राशि के विकास कार्यों लोकार्पण करेंगे। इनमें 48.03 लाख की लागत से अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, तोकापाल और लोहांडीगुड़ा तथा 66.49 लाख की लागत से नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार के साथ 2.50-2.50 करोड़ की लागत से निर्मित लोहांडीगुड़ा और बुरगुम थाना का शामिल हैं। इसी प्रकार जिला अस्पताल (महारानी अस्पताल) परिसर में डीएमएफटी मद के तहत 01 करोड़ 72 लाख 76 हजार की लागत से स्थापित माडुलर किचन एवं सामग्री युक्त अन्नपूर्णा रसोईघर का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही महारानी लक्ष्मी बाई अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ किया जाएगा।

माओवाद उन्मूलन के रास्ते पर बढ़ चुका है छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री

डायमंड स्टेट कार्यक्रम में विष्णुदेव साय का संबोधन

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब माओवाद उन्मूलन के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। हम राज्य में माओवाद प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। माओवाद के रास्ते को छोड़कर वापस लौटने वालों के लिए हम बेहतर पुनर्वास नीति तैयार करेंगे और इसके लिए हमारे गृह मंत्री असम प्रवास पर भी हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने न्यूज 18 के डायमंड स्टेट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में 150 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षाबलों के हौसले बुलंद है। गोली का जवाब गोली और बोली का जवाब बोली से ही दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना साकार करने के लिए ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। नवनिर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर विकास के रास्ते आगे बढ़ रहा है। साय ने कहा कि प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने किसानों को धान के दो वर्षों का बकाया बोनस, 3100 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी, माता-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रति माह 1 हजार रूपये की राशि देने का काम हम कर रहे हैं।

श्री साय ने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच कराई जा रही है और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ के घर-घर में नल से जल की व्यवस्था करने का काम, अमृत मिशन के माध्यम से जल पहुंचाने का काम, बिजली, पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं, धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना से लोगों जीवन को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शौचालय मान-सम्मान से जुड़ा विषय था। बरसात के दिनों में जो कठिनाइयां माता बहनों को होती थी, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की।

आज इस मिशन से देश में बड़ा परिवर्तन लाया है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना और शक्तिपीठ सर्किट के निर्माण के संबंध में भी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने व्यक्तिगत जीवन संघर्ष और राजनीतिक जीवन से जुड़ी जानकारियां भी दी।

किसी की जाति-धर्म पूछना अपराध नहीं: गिरिराज सिंह

नई दिल्ली। संसद में राहुल गांधी की जाति पूछने को लेकर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी की जाति धर्म पूछना कोई अपराध नहीं है। अगर राहुल गांधी को यह गलत लगता है तो वह मामला दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने को विपक्ष का राजनीतिक ड्रामा करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनकी जाति पूछता है तो उनको बुरा लगता है। अगर यह गलत है तो आप मामला दर्ज करें। यह अच्छा है कि राहुल गांधी जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपकी जाति और धर्म क्या है यह देश जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही पिछड़ी जातियों के सशक्तीकरण के लिए काका कालेलकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाए रही। जबकि भाजपा जातिगत जनगणना की समर्थक थी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को सदन में वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए ट्रेन के किराये में 50 फीसदी छूट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बंद की गई छूट को फिर से शुरू किया जाए।

ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता: मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा उनकी राजनीतिक यात्रा पर की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए कहा, जिसमें उल्लेख किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा परिवार राजनीति में शामिल था। उन्होंने परिवारवाद के संबंध में एक टिप्पणी की। खड़गे ने कहा, अनुरोध है कि इसे (रिकॉर्ड से) हटा दिया जाना चाहिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह तिवारी द्वारा मंगलवार को सदन में की गई टिप्पणियों पर गौर करेंगे और आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेता को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी शब्द रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। खड़गे ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि वह पहली पीढ़ी के राजनेता थे जिन्होंने अपना करियर कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था। उन्होंने बताया कि उनके पिता का 85 साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके जवाब में चेयरमैन धनखड़ ने खड़गे की लंबी उम्र की कामना की, जिस पर खड़गे ने कहा, मैं इस माहौल में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहता। सदन में एक सूचीबद्ध पेपर की प्रस्तुति के बाद, खड़गे ने तिवारी द्वारा की गई टिप्पणियों को संबोधित किया, जिन्होंने खड़गे के राजनीतिक करियर पर टिप्पणी की थी और उल्लेख किया था कि खड़गे का पूरा परिवार राजनीति में शामिल था।

विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कृषि मंत्री ने नवा रायपुर के शासकीय आवास एम-5 में किया गृह प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम आज शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अटल नगर नवा रायपुर स्थित नवीन शासकीय आवास एम-5 में गृह प्रवेश किया। मंत्री रामविचार नेताम को इस मांगलिक अवसर पर नवा रायपुर पहुंचकर बधाई देने वालों में महामहिम राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, अरुण साव तथा मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण शामिल रहे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शासकीय आवास में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया।

प्रमुख समाचार

प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट-टीचर मीटिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह नियमित रूप से पैरेंट-टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव, सिद्धार्थ कोमल परेदशी ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए एक पत्र जारी किया है। जिसके मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग का आयोजन 6 अगस्त 2024 को संकुल स्तर पर किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव, सिद्धार्थ कोमल परेदशी द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी किये गए पत्र के अनुसार, प्रत्येक संकुल में बैठक के पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करने और जिला स्तरीय टीम द्वारा भौतिक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान, 12 निर्धारित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और शिक्षकों का चिन्हांकन कर उनका उन्मुखीकरण कराया जाएगा, ताकि वे पालकों को सही जानकारी प्रदान कर सकें। बैठक के दौरान शिक्षक, शासन द्वारा संचालित विद्यार्थी हितग्राही योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि पालक और विद्यार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बीच भारत-चीन ने की कूटनीतिक वार्ता

नई दिल्ली। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लंबे समय से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के लिए बुधवार को कूटनीतिक वार्ता की। वार्ता भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने के उद्देश्य से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शांति और स्थिरता की बहाली तथा एलएसी के प्रति सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक आधार हैं। दोनों पक्षों ने सरकारों के बीच प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल और सहमति के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में चर्चा गहन, रचनात्मक और दूरदर्शी रही।

6922 करोड़ मिलने पर सांसद पांडेय ने रेल मंत्री का जताया आभार

नई दिल्ली। लोकसभा के बजट सत्र में राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय ने रेल के क्षेत्र में विकास के लिए छत्तीसगढ़ को प्राप्त 6922 करोड़ के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. सांसद पाण्डेय ने कहा कि साल 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य को दक्षिण पूर्व मध्य रेल के माध्यम केन्द्रीय बजट में मात्र 311 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जबकि साल 2024 में 6922 करोड़ प्राप्त हुए हैं. बजट में 22 गुना वृद्धि कर रेल के क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने में केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है. उन्होंने आगे बताया कि राज्य के 32 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना में शामिल कर नवीनीकरण व उन्नयन का कार्य जारी है. साथ ही 37018 करोड़ की लागत से 25 नयी रेल परियोजनाओ पर कार्य जारी है. छत्तीसगढ़ में 141 ओवरब्रिज व अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसमें से 14 राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से हैं. डोंगरगढ़ से कटघोरा नवीन रेल लाइन को गति प्रदान करने के विषय को सदन में रखते हुए सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि इस नवीन रेल लाइन का जल्द निर्माण कार्य चालू होना आवश्यक है, जिससे मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर रेल ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम होगा.

बृजमोहन ने कोयला उत्पादन बढ़ाने व आयात कम करने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। देश में कोयले का घरेलू उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला मंत्रालय लगातार कार्य कर रहा है। लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। जिसके मुताबिक कोयला आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेशकश की गई कोयले तथा एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

या तो आप रहोगे या मैं, उद्धव ठाकरे की फडणवीस को चुनौती

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता और मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ठाकरे ने कहा कि या तो आप वहां नहीं रहेंगे या मैं वहां नहीं रहूंगा। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें बताया था कि कैसे फणडवीस ने उन्हें और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रची थी। उद्धव ने कहा कि वह सभी बाधाओं को झेलकर भाजपा नेता के सामने मजबूती से खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख ने बताया कि कैसे फड़णवीस ने मुझे और आदित्य को जेल में डालने की साजिश रची थी। सब कुछ सहने के बाद, मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। या तो आप (फडणवीस) होंगे या मैं वहां रहूंगा। इसके अलावा, उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि कैसे अन्य नेताओं ने उन्हें भाजपा के शीर्ष नेता के खिलाफ बोलने से परहेज करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह व्यक्त करेंगे कि भगवा पार्टी ने राज्य में क्या किया है।

बाबू भैया की कलम से ✍

आरक्षण और राज्यपाल : घाव पुराना-दर्द नया

छत्तीसगढ़ को नया राज्यपाल मिल गया। रामेन डेका ने आज राजभवन में पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा ने उन्हें प्रदेश के मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह,पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसदों, मंत्रियों, विधायकों व सभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में शपथ दिलाई। उन्होंने सबसे मुलाकात कर परिचित होने का प्रयास किया। निवृतमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कल शानदार बिदाई दी गई। उनके कार्यकाल की सभी ने तारीफ की। लेकिन कांग्रेस ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का दर्द भी महसूस किया। राज्यपाल बदलते ही आरक्षण का जिन्न फिर से बोतल से निकल रहा है। कांग्रेस के ओबीसी नेता धनेंद्र साहू ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में उक्त आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था ,लेकिन उसे न ही तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने और ना ही निवृतमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने कार्यकाल में अनेक आग्रह किये जाने के बाद भी हस्ताक्षर किये। अब हमें नए राज्यपाल से काफी उम्मीदें हैं। हम कांग्रेस के एसटी,एससी,ओबीसी विधायक व वरिष्ठ नेतागण जल्द ही राज्यपाल रामेन डेका से मिलकर आरक्षण पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करेंगें। सबकी सहमति से विधानसभा में तीन साल पूर्व पारित इस महत्वपूर्ण आरक्षण के मामले को तत्कालीन राज्यपाल उइके ने सरकार को दिए कथित मौखिक आश्वासन के बावजूद हस्ताक्षर नहीं किये। ना ही लौटाया। ना ही उसका कारण ही बताया। वैसे आरक्षण के मुद्दे पर 2012 से सियासत जारी है। आज तक वह सियासत समाप्त ही नही हो पा रही है। नए राज्यपाल के आगमन व उनके शपथ ग्रहण के साथ ही यह आरक्षण का जिन्न फिर बोतल के बाहर आता दिखाई दे रहा है। लगने लगा है कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित इस मामले में सियासती तौर पर कांग्रेस व भाजपा फिर आमने सामने होंगी। इस महत्वपूर्ण विधेयक में तात्कालीन कांग्रेस सरकार ने एसटी वर्ग को 32 प्रतिशत,एससी वर्ग को 13 प्रतिशत,ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी शामिल करते हुए उन्हें भी 4 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वाकांक्षी प्रावधान किया था.इस तरह कुल 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को काफी बहस के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से सबने मिलकर पारित कराया था। हालांकि विधेयक में अपनी अनेक आशंका-कुशंकाओं को भाजपा ने सदन में जाहिर किया था। आशिंक विरोध भी दर्ज करते हुए कहा था कि, इससे भविष्य में कानूनी अड़चने आएंगी। अंतत: सियासी लाभ हानि को देखते हुए भाजपा ने इस पर सदन में सहमति दे दी या कहें कि राजनैतिक मजबूरी में देनी पड़ी। अब गेंद राजभवन के पाले में थी जहां से कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को कथित आश्वासन मिला था कि सदन से विधेयक पारित होते ही हस्ताक्षर हो जाएंगे। सरकार के मंत्रीगण रात में ही पारित विधेयक को लेकर राजभवन पहुंच भी गए। प्रस्तुत किया लेकिन राज्यपाल ने विधेयक पर विचार करने की बात कह कर मंत्रियों को चौंकाने का काम किया। तब से लेकर आज तक उक्त विधेयक प्रावधानों के विरुद्ध राजभवन में लंबित है। न हस्ताक्षर हुए ना लौटाया,ना ही कारण बताया। कांग्रेस ने इस मामले में राजभवन को भी सियासत करने का आरोप लगाते हुए घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी बात को लेकर इस मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा में सियासी तकरार थम नहीं रही है। नए राज्यपाल के आगमन के बाद अब फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस राज्यपाल से इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करने मुलाकात करने जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस भाजपा पर आरोपों का पिटारा खोलेगी,कहेगी ये लोग आरक्षण के विरोधी हैं। राज्यपाल से मिलकर आरक्षण पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करने भाजपा पर दबाव भी बनाने की सियासत होगी। उसे एसटी,एससी ,ओबीसी विरोधी बताया जाएगा। इधर सरकार के कद्दावर मंत्री रामविचार नेताम ने आरक्षण संशोधन विधेयक को विवादित तथा कांग्रेस का राजनैतिक स्टंट बताकर और विवाद का रास्ता बना दिया। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल इसका परीक्षण कर लेंगें। इनके बयान पर प्रश्न यह उठेगा कि जब यह विधेयक विवादित था, तो इस पर सदन में भाजपा ने भी सहमति क्यों दी थी। सर्वसम्मति कैसे बनी। आरक्षण का मुद्दा फिर उठ गया है आते ही नये राज्यपाल रामेन डेका के सामने निष्पक्ष दिखने की चुनौती खड़ी हुई है। ऐसे में इन वर्गों की निगाहें व आम जनों की नजर राजभवन के ऊपर होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आरक्षण पर राजभवन में कोई फैसला हो पायेगा या यह विधेयक संविधान के धाराओं में वर्णित नियम नीतियों ,अधिकारों से ऊपर होकर अनन्तकाल तक यू हीं लंबित रहेगा। कुल मिलाकर नये राज्यपाल के आगमन ने इस मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है।

कांग्रेस को अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने का बेहतर मौका मिला है,जिसे भुनाने कांग्रेस के वरिष्ठ ओबीसी नेता धनेंद्र साहू ने पहल कर दी है। मुद्दा कांग्रेस में जान फूंकने वाला साबित हो सकता है। देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस संगठन व अन्य कांग्रेस के नेता उनका इस मामले में कितना साथ देते हैं। साहू का उठाया मुद्दा पार्टी का मुद्दा बनता है कि नहीं।

जल संसाधन विभाग की लापरवाही से किसानों को परेशानी

आरंग। आमतौर पर हमेशा देखा जाता है कि शासकीय विभाग मानसून के पूर्व अपनी तैयारियां पूरी कर लेता है, जिससे बरसात में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे तो जल संसाधन विभाग बना है किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए लेकिन रायपुर जल संसाधन विभाग को किसानों की कोई चिंता नहीं है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा आरंग सहित जिले के हजारों किसानों को भुगतना पड़ सकता है। खरीफ फसल में किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए जिस नहरों और माइनर की सहायता ली जाती है, अब तक इनकी सफाई नहीं हो पाई है। जल संसाधन विभाग द्वारा उचित रखरखाव नहीं होने से यहां खरपतवार और कचरे का अंबार लगा हुआ है। यही स्थिति पूरे क्षेत्र में है।

रायपुर डिवीजन के अंतर्गत सब डिवीजन आरंग 04 के लखौली मेन केनाल से वितरक शाखा के माइनर पूरे आरंग क्षेत्र में फैला हुआ है। इससे गंगरेल बांध से खरीफ फसल के किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। लेकिन विभाग के उदासीनता और लापरवाही के कारण अभी तक नहर और माइनर की सफाई नहीं हो पाई है। रखरखाव के अभाव में नहर और माइनर, खरपतवार और कचरे से पटा हुआ है। विभाग की ओर से समय-समय पर इसको साफ करने की बात कही जाती है लेकिन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते है। अगर विभाग द्वारा समय-समय पर इसका रखरखाव किया जाता तो खरपतवार और कचरे का अंबार भी नहीं लगा होता।

क्षेत्र के किसानों ने बताया कि काफी लंबे समय के नहरों और माइनर की सफाई नही हुई है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर देते है। किसानों ने बताया की कई बार सफाई के लिए नगर पालिका के जेसीबी की मदद ली जाती है और स्वयं के व्यय से सफाई कराना पड़ता है।विभाग द्वारा उचित रखरखाव नहीं किया जाता है।अगर नहर और माइनर की देखरेख विभाग द्वारा की जाती तो खरपतवार और कचरे का अंबार नही लगा होता।किसानों ने बताया कि सफाई नही होने से अंतिम छोर से किसानों पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाता है।जब गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जाता है तो सफाई नही होने से पानी माइनर के ऊपर से बहने लगता है जिससे पानी कही भी घुस जाता है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि रायपुर डिवीजन के अंतर्गत आरंग सब डिवीजन है, जिसमें लखौली केनाल से आरंग क्षेत्र के हजारों किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। कायदे से आरंग सब डिवीजन होने से आरंग में ही इसका कार्यालय होना था लेकिन इसका कार्यालय रायपुर में है।किसानों को अपनी हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए रायपुर जाना होता है,अगर वहां भी संबंधित अधिकारी से मुलाकात हुई तो काम होता है वरना किसानों को निराशा हाथ लगती है।

इस पूरे मामले में आरंग में जिम्मेदार अधिकारी नहीं होने के कारण मीडिया ने जल प्रबंध 01 के कार्यपालन अभियंता (ईई) ललित रावटे,अनुविभागीय अधिकारी आरंग (एसडीओ) पी.के.पाल से मोबाइल के माध्यम संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया।

प्रदेश में किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। किसान हर परिस्थिति से लड़कर खेतों में फसल उगाता है लेकिन किसान हर बार ठगा जाता है। अगर किसान इन्हीं समस्याओं में पड़ा रहा तो खेती - किसानी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। इसी कारण किसान अपनी पीड़ा बिना किसी को बताए अपना कार्य नि:स्वार्थ भाव से करता है।अगर शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी अपना कार्य जिम्मेदारी, ईमानदारी और नि:स्वार्थ भाव से करे तो प्रदेश में किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी।

विकास की राह तकता गांव, कीचड़ भरे रास्ते से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के मजबूर बच्चे

- **जनप्रतिनिधियों से गुहार के बाद भी नहीं बनी सड़क**

गरियाबंद। मैनपुर ब्लॉक के धोबन माल पंचायत के आश्रित ग्राम डोंगरी भांठा में बरसात के दिनों में सड़क की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। 600 की आबादी वाले इस गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं है। गांव से लेकर पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने कीचड़ से लथपथ सड़क हो कर जाना पड़ता है। इसी बीच आधे किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल भी है। जहां पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को बारिश भर कीचड़ से लथपथ होकर आना पड़ता है। ग्रामीण गोवर्धन मरकाम ने बताया कि सड़क के लिए सांसद से लेकर विधायक तक शासन से लेकर प्रशासन तक मांग किए पर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया।

मितानिन खिरमती बाई ने बताया कि बारिश के दिनो मे सुरक्षित प्रसव कराना किसी चुनौती से कम नही होता।गांव के बाहर जाने वाले सभी सड़क कीचड़ से लथपथ रहता है। पैदल चलना दुभर हो जाता है,बारिश के समय हादसे में कई बार जच्चे बच्चे को नुकसान हो चुका था, इसलिए अब समय से पहले गांव से बाहर परिजनों के घर आश्रय लेकर गर्भवती को रखना पड़ता है।

गांव के बुजुर्ग पूरन सिंह और धनु राम मरकाम ने कहा की यह आदिवासी बहुल गांव है, 400 वोटर भी है। भाजपा कांग्रेस के कई आदिवासी नेताओं को हम अब तक वोट देते आए हैं। चुनाव के समय ही वे दिखते हैं,वादा भी करते हैं सड़क बनाने का,लेकिन हमको केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले नेता हमारी इस समस्या को दूर नही किया।पिछले 20 साल से सड़क की मांग हो रही है।

मामले में पंचायत सचिव विनोद बिहारी ने बताया कि पिछले साल 5 लाख का मुरमीकरण किया गया था। लेकिन इस बार जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन खोदने वालों ने सड़क में कीचड़ डाल दिया।

क्षमता से अधिक कैदियों को जेल में रखने का मामला

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब

बिलासपुर। प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। जिसमें बताया गया है कि रायपुर और बिलासपुर जिले में विशेष जेलों की स्थापना की जा रही है। साथ ही बेमेतरा में खुली जेल शुरू की जा रही है। मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

अधिवक्ता शिवराज सिंह ने केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है। जिसके कुछ समय बाद कैदियों के लिए जेलों में अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक पीआईएल लगाई गई है। वहीं हाईकोर्ट के संज्ञान में भी यह बात आई कि जेलों में कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे अदालत ने स्वयं एक पत्र याचिका के तौर पर स्वीकार किया है। मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई शुरू की गई, और कोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया।

मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कहा था कि रायपुर जिले में विशेष जेल हेतु भूमि मिल चुकी है, और काम शुरू कर दिया गया। बेमेतरा में भी एक खुली जेल की स्थापना की जा रही है, इसमें काम अंतिम चरण पर है। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन का जवाब आया, जिसके बाद अब मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।

सीएम कैंप कार्यालय बगिया से महादेव को मिला श्रवण यंत्र

जशपुरनगर। कांसाबेल तहसील के शबदमुंडा गांव के रहने वाले 75 वर्षीय महादेव यादव को सीएम कैंप कार्यालय से श्रवण यंत्र दिया गया। जिससे अब वह बहुत खुश है। उसने खुश होकर कहा कि अब वह भी हर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुन सकेगा।जशपुर जिले के बगिया में स्थापित सीएम कैंप कार्यालय का लाभ निरंतर हर वर्ग के लोगों को प्राप्त हो रहा है। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करा कर थक चुके परिजन अब आस लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंच कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, और कार्यालय द्वारा उनका त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांसाबेल ब्लॉक के शबदमुंडा गांव के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग महादेव यादव के कानों में समस्या थी, वह ठीक से सुन नहीं पाता था। बुधवार को वह अपनी समस्या लेकर सीएम कैंप कार्यालय, बगिया पहुंचा था। जहां उसने आवेदन देकर श्रवण यंत्र दिलवाने की गुहार लगाई। सीएम कैंप कार्यालय ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई और वहां की पहल पर तत्काल ही महादेव यादव को श्रवण यंत्र प्रदान कर दिया गया। महादेव अब बहुत खुश है कि अब उसे भी आसानी से सुनाई देगा और वह बिना परेशानी के लोगों से बात कर सकता है। इसके लिए उसने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है।

प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निजी निवास बगिया को सीएम कैंप कार्यालय घोषित किया गया है,जिसके बाद यहां लोग आसानी से अपनी समस्या सुनाने पहुंचते है,और उनकी न केवल समस्या सुनी जाती है,बल्कि गंभीरता पूर्वक मौके पर ही त्वरित निराकरण भी किया जाता है,जिससे लोगों का यह सीएम कैंप कार्यालय आशा का केंद्र बना हुआ है।

पंडित प्रदीप मिश्रा का धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान

- **लंबी उम्र जीने का बताया आसान तरीका**

भिलाई। भिलाई के जयंती स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। कथा के छठवें दिन मौसम साफ रहा।जिसके कारण करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया।कथा के प्रांगण स्थल में जितने भक्त थे,उससे कहीं ज्यादा भक्त पंडाल के बाहर थे।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय और उनके पुत्र तोशेन्द्र साय ने भी कथा का श्रवण किया।

सीएम साय की पत्नी पहुंची कथा श्रवण करने - आपको बता दें, कौशल्या साय लगातार पांचवें दिन कथा स्थल में कथा सुनने पहुंची थीं। इनके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, भिलाई निगम महापौर नीरज पाल, दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई भाजपा अध्यक्ष महेश वर्मा, पूर्व अध्यक्ष बृजेश ब्रिजपुरिया, पार्षदगण, दुर्ग सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल भी मौजूद थी। बुधवार 31 जुलाई की कथा का अंतिम दिन है। जो सुबह 8 बजे शुरू होगा और 11 बजे खत्म होगा।

पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि छत्तीसगढ़ क्या भारत की किसी भी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने इससे पहले कोई भी कथा चार-पांच दिन तक लगातार बैठकर पूरी नहीं सुनी होगी। कौशल्या जी ना सिर्फ शिव महापुराण का श्रवण कर रही हैं, साथ ही लोगों को प्रेरित कर रही है कि कितने भी बड़े पद पर हो पर भगवान की भक्ति नहीं भूलनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह की तारीफ की।

प्रदीप मिश्रा ने कहा कि चार-पांच दिन में तो लोग शादी की व्यवस्था नहीं कर पाते।लेकिन दया सिंह और उनकी समिति के सभी लोगों ने चार से पांच दिन में लाखों लोगों की तादाद वाली शिव महापुराण कथा की व्यवस्था कर दी। लोग भंडारा करते हैं, पूजा करते हैं पर दया सिंह जी ने लाखों लोगों को शिव महापुराण का भंडारा करा दिया। इसके लिए उनका साधुवाद। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जब मैं भिलाई पहुंचा तो पहले दिन से जब दया सिंह जी ने मुझे एयरपोर्ट से लेने आए थे। तब से उन्होंने आज तक हर दिन मुझे कहा कि महाराज जी हर साल हमारे भिलाई वालों के लिए कथा करने जरूर आए। इस दौरान बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह से कहा कि ओंकारेश्वर या फिर अन्य जगहों से शिवलिंग लाकर छोटे-छोटे ग्रामों में स्थापित करवाएं। ताकि गांव में जो धर्मांतरण हो रहा है, ऐसे लोग भी शिवजी की शरण में आ जाएं।

शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझे, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी से आप ग्रसित हो कितने बार भी आप हार जाए, कोई भी विषम परिस्थिति में जो मुस्कुराता है भोलेनाथ उसका साथ देता है। आप जिस दिन खुद को कमजोर समझना शुरू कर देंगे तो आप समझ लेना कि आप पापी हो। जरा सा पेट दुखा या छाती में दर्द हुआ तो आप सोच लेते हैं कुछ तकलीफ हो गया है ऐसे में आपने पहले से ही सोच लिया कि मुझे तकलीफ है। इलाज कराने भी आप जा रहे हो तो ये सोच कर जा रहे हो कि मुझे तकलीफ है। इस प्रकार आप अपने अंदर यह अलार्म लगा ले रहे हो कि आपको कुछ तकलीफ है।

पहले के लोग अपना अलार्म लगाते थे कि कम से कम में 100 साल जीना है, इसलिए वे कम से कम वह 90-95 साल जीते थे। लेकिन आज के दौर में लोग अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं कि मुझे कुछ तकलीफ हो गई है, तो जरूर कुछ बड़ा होगा।अपने आप को प्रबल समझिए अपने आप को स्ट्रांग रखिए। छोटी-मोटी बीमारी आती जाती है पर कमजोर नहीं पड़ना है। जो व्यक्ति अपना कर्म करते रहता है, उसकी मेहनत का फल उसको भगवान एक दिन जरूर देता है। जैसे एक चींटा अपना कर्म करते रहता है, भगवान उसको एक दिन पंख लगा देता है और वो उड़ने लगता है। ध्यान रखना इसी तरह आपको भी अपना कर्म करना है, परमात्मा आपको भी पंख लगा कर आगे बढ़ाएगा, आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

झमाझम बारिश से जलभराव, नाले उफने और बिजली भी गुल

कोरबा। नगर निगम क्षेत्र के अमरिया पारा में जलभराव से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई घरों की हालत जर्जर है। मूसलाधान बारिश में वे गिर सकते हैं। इसके अलावा रास्तों पर पानी भरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। अगर नगर निगम के अफसरों ने समय से जलनिकासी की व्यवस्था कराई होती तो आज ये हालात न होते। इसके अलावा यहां डेंगू और मलेरिया फैलने की भी आशंका है। इसी तरह दादर खुर्द मुख्य मार्ग पर देर रात हुई झमाझम बारिश से नाला ओवरफ्लो हो गया। नाले का पानी सड़क पर आने से पता ही नहीं चल रहा है कि कहां सड़क है और कहां नाला। इस कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। रात भर आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी है। मुड़ापार, पोड़ी बहार, काशी नगर के कई इलाकों में बिजली नहीं होने से लोग परेशान हैं। यही हाल एसईसीएल कॉलोनी क्षेत्र में भी है। रात को गई बिजली सुबह तक भी नहीं आ सकी थी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सूची जारी

जगदलपुर। जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना बकावंड-01 और 02 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अंतिम योग्यता सूची जारी किया गया है। उक्त सूची का अवलोकन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है। जिसके तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना बकावंड-01 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंन्द्र चोलनार आवासपारा, चोलनार क्रमांक-1 खासपारा, चोलनार आमागुड़ा, उडियापाल क्रमांक-1, उडियापाल क्रमांक-2, पाहुरबेल क्रमांक-1, सतलावंड और तारापुर क्रमांक-5 में आंगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं एकीकृत बाल विकास परियोजना बकावंड-2 के अंतर्गत चारगांव तलपारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छिन्दगांव आमागुड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा चारगांव तलपारा, छिन्दगांव आमागुड़ा, बेलपुटी पाथरियागुड़ा, बेलपुटी क्रमांक-2 गोटीगुड़ा, धनपुर, संवरा क्रमांक-1, सतोषा क्रमांक-3 और सरगीगुड़ा में आंगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति की जानी है।

पुलिस ने देखा जादू, वर्दीवालों को जादूगरों ने सिखाए ट्रिक्स

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस लाइन मैदान में मंगलवार को जादू खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र से आए जादूगरों ने जादू का खेल दिखाकर पुलिस जवानों और उनके परिवार का मनोरंजन किया। बलरामपुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में पुलिस कल्याणकारी गतिविधि के तहत जादू के खेल का आयोजन कराया गया। जिसमें नागपुर महाराष्ट्र के कलाकारों जादूगर नजीर खान और जादूगर रहमान ने अपने हाथों की सफाई और कला दिखाई। जादूगरों ने जादू दिखाकर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में उपस्थित पुलिस स्टाफ और परिवार के सदस्यों और बच्चों का जमकर मनोरंजन किया। बलरामपुर जिले के रक्षित निरीक्षक विमलेश देवांगन ने बताया कि नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस लाइन में जादू का खेल दिखाने का कार्यक्रम रखा गया। नागपुर से दो जादूगर यहां जादू का खेल दिखाने आए हैं। यहां पुलिस लाइन कॉलोनी के बच्चे, माता-पिता और अभिभावक सभी लोग पहुंचे।

भाटापारा में चोरों का आतंक मंदिर में चोरी, तोड़ा ताला

भाटापारा। भाटापारा में चोरों का आतंक

कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गांधी मन्दिर वॉर्ड में स्थित रिलायंस ट्रेंस में अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फस्ट फ्लोर एवं ग्राउंड फ्लोर पर सामान बिखरा हुआ मिला। टुटे ताले को देखकर स्टोर मैनेजर शिवनंदन ने भाटापारा शहर थाने में चोरी होने की शंका में शिकायत की। भाटापारा शहर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। दो दिन पहले भी शहर में लगभग 20 लाख रुपये चोरी कर फरार चोर का पुलिस नहीं खोज पाई है। शहर के बीचों बीच चोरी के प्रयास की दूसरी घटना हुई। शहर के लोगो में दहशत का माहौल है।

दिनदहाड़े करता लूटपाट, चोरी से पहले घर छोड़ जाता मोबाइल

दुर्ग। जिले में पिछले कुछ माह से चेन स्नेचिंग के कई घटनाएं घटित हुई। घटना के बाद पुलिस लगातार इस की तफ्तीश में जुटी हुई थी। पुलिस ने इन वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस मामले में महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में चेन स्नेचिंग के सात वारदात को अंजाम दिया था। भिलाई शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि दुर्ग पुलिस ने एक चेन स्नेचिंग करने वाले को गिरफ्तार किया है जो भिलाई के विभिन्न थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोर वारदात को अंजाम देते समय अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ देता था। चोरी की बाइक से घटना को अंजाम देता था। आरोपी भरत गुप्ता हथखोज को गिरफ्तार कर किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि भिलाई के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सात चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पिछले छह महीने में भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की थी।

कोयलीबेड़ा का बेवड़ा डॉक्टर, इलाज के लिए भटक रहा था परिवार

- **शराब पीकर लोट रहा था जिम्मेदार**

कांकेर। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या है,इसका जीता जागता उदाहरण कोयलीबेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। जहां शराब के शौकीन डॉक्टर की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। मासूम के परिजन का आरोप है कि जिस वक्त वो अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई भी डॉक्टर नहीं था।मालूम करने पर पता चला कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कहीं गए हैं।लेकिन जब डॉक्टर को खोजा गया तो वो नशे में धुत सड़क पर लोट रहा था।

कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलीबेड़ा में 6 एमबीबीएस डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं। यहां कार्यरत 4 में से एक डॉक्टर को अंतागढ़ अटैच किया गया है।जबकि दो डॉक्टर पीजी करने गए हैं। एकमात्र डॉक्टर शीतल दुग्गा के कंधों पर स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी है।लेकिन इसे बदकिस्मती कहेंगे कि ये डॉक्टर शीतल दुग्गा अंगूर की बेटी के दीवाने हैं। इसलिए ये ड्यूटी के दौरान भी अंगूर की बेटी का स्वाद लेकर सड़क पर लोटते रहते हैं। इन्हें अपने हॉस्पिटल के केबिन से ज्यादा सड़क प्यारा है।फिर चाहे वो कीचड़ से सना हो या गोबर से।ये पीकर लोटेंगे ही। इनके इसी शौक ने आज एक मासूम की जान ले ली है।

ये पूरी घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। टीकेश पटेल अपने बेटे मयंक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। मयंक के पेट में तेज दर्द था। मौके पर कोई भी डॉक्टर मौजूद ना होने के कारण बच्चे को बिना इलाज के ही रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई।इस दौरान जब डॉक्टर शीतल दुग्गा को ढूंढा गया तो वो कोयलीबेड़ा के सड़क पर नशे में लोटते हुए नजर आए।जिसका वीडियो परिजनों ने बना लिया।जब इस बात की जानकारी डॉक्टर शीतल को हुई तो आग बबूला हो गए।इसके बाद शीतल दुग्गा ने गाली गलौज पर उतर आए।

पूरा मामला सामने आने के बाद सीएमएचओ अविनाश खरे ने डॉक्टर शीतल दुग्गा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। डॉक्टर संविदा पद पर था। जिसकी सेवा समाप्त करने शासन को पत्र लिखने की बात भी सीएमएचओ ने कही है। इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए उन्होंने अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कोयलीबेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में दूसरे डॉक्टर को भी पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

बदहाल सड़क को लेकर कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिला मुख्यालय का प्रसिद्ध इतवारी बाजार की सड़कें सालों से बदहाल हैं। बारिश के मौसम में स्थानीय लोगों को सड़क सुविधा के बिना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालातों को देखते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी ने बरसते पानी में सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और इतवारी बाजार चौक में ही धान का रोपा लगा कर विरोध दर्ज किया है।

बता दें, जिले के मुख्य बाजार यानी इतवारी बाजार में बेहतर सड़क सुविधा के लिए स्थानीय लोगों ने इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है। लेकिन अब तक सड़कों की स्थिती जस की तस है। वहीं आज इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और भारी बारिश के बीच ही कांग्रेसी सड़क पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने इतवारी बाजार चौक की सड़क पर धान का रोपा लगाया और ज्ञापन लेने पहुँचे अधिकारी को बेशर्म का फूल देकर अपना विरोध जताया है।

इस मामले में विधायक मनराखन देवांगन ने बताया कि शहर के सभी मुख्य मार्गों में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके चलते राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे इस बदहाल सड़क से परेशान हैं, जिसे लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन ने यहाँ जीरा गिट्टी डालकर खानापूर्ति की है, लेकिन हमें इसका स्थाई समाधान चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसका स्थाई समाधान नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे और विधायक खैरागढ़ के माध्यम से सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे।

छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल ने संभाला पदभार, डेका ने ली पद और गोपनीयता की शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नये राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को राजभवन में प्रदेश के दसवें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान साय कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने डेका से दरबार हाल में एक-एक करके मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी।

समारोह में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड के बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य गीत की धुन भी बजाई गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वित्तमंत्री ओपी चौधरी, वन एवं जलवायु परिवर्तन केदार कश्यप, वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल रमेन डेका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। वे सन् 1977 से राजनीति में सक्रिय हैं। वे वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। रमेन डेका वर्ष 2006 में असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। डेका 2021 अगस्त माह से असम राज्य के नवाचार एवं रूपान्तरण आयोग के (कैबिनेट मंत्री का दर्जा) के उपाध्यक्ष पद पर 29 जुलाई 2024 तक रहे है।वे दो बार सांसद रहे। पहली बार वर्ष 2009 में 15 वी लोकसभा के लिए असम के मंगलदोई सीट से सांसद चुने गये थे। इस दौरान वे गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य, लोक लेखा के सदस्य, भारत भुटान संसदीय मैत्री समूह सदस्य, अधीनस्थ विधान समिति सदस्य, सदन की बैठको से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति सदस्य रहे। उसके बाद वर्ष 2014 में वे 16 वीं लोकसभा के लिए दुबारा सांसद निर्वाचित हुए। दूसरे कार्यकाल में वे डेका लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल के सदस्य भी रहे।

इस दौरान सदस्य अनुमान समिति, सदस्य सलाहकार समिति, सदस्य विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामले, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य, भारत-चीन संसदीय मैत्री समूह सदस्य, चाय बोर्ड के सदस्य का दायित्व निर्वहन किया। दूसरे कार्यकाल में ही सदस्य गृह मामलों की स्थायी समिति, सदस्य सामान्य प्रयोजन समिति, सदस्य उप समिति द्वितीय अनुमान समिति, सदस्य विदेश मामलों की स्थायी समिति रहे और 2021 से अभी तक नवाचार रूपान्तरण आयोग असम के उपाध्यक्ष रहे।

डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची, कामरूप (असम) में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ डेका और माता का नाम स्वर्गीय चंपाबती डेका है। उनके परिवार में धर्मपत्नी रानी डेका काकोटी एवं दो बच्चे हैं। उन्होंने बीए की डिग्री दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में प्राग्ज्योतिष कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम से प्राप्त की।

इससे पूर्व डेका और उनकी धर्मपत्नी रानी डेका काकोटी के छत्तीसगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्टेट हेंगर में आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर मनोनीत राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। यहां विकास को नये स्तरों पर पहुंचाने हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो। उन्होंने कहा कि वे असम और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए भी काम करेंगे। डेका ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के विकास को लेकर है। स्टेट हेंगर पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों सुआ, कर्मा, डंडा और राउत नाचा से किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने भी पुष्पगुच्छ भेंटकर राज्यपाल का अभिवादन किया। साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी राज्यपाल का अभिवादन किया।

मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका ने मां काली से लिया आशीर्वाद

छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल श्री रमेन डेका ने बुधवार प्रात: आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर में जाकर दर्शन-पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मनोनीत राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती रानी डेका काकोटी एवं अन्य परिजन उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा इन दिनों असम के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आज डिप्टी सीएम शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से उनके निवास में मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तस्वीर साझा की और लिखा, 'आज असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से उनके निवास पर भेंट कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनके नेतृत्व में असम शांति, विकास और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई'।

दो वरिष्ठ अधिवक्ता होगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीडी गुरु व एके प्रसाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए जस्टिस होंगे। छत्तीसगढ हाईकोर्ट कालेजियम ने इन्हे जस्टिस बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम को प्रस्ताव भेजा था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इनकी नियुक्ति होते ही हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी।

विशेष ट्रेन से रामलला के दर्शन, हर सप्ताह अयोध्या जा रहे श्रद्धालु

रायपुर। राम भक्तों का जत्था लगातार अयोध्या धाम पहुंच रहा है। 30 जुलाई को धमतरी जिले के 133 श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना हुए। वहीं गरियाबंद जिले से भी 94 श्रद्धालु रवाना हुए। वहीं 23 जुलाई को भी दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को दुर्ग स्टेशन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ में श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईआरसीटीसी के बीच विशेष ट्रेन चलाने और जरुरी व्यवस्था के लिए एमओयू हुआ है। श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक हर सप्ताह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन में 12 कोच हैं। एक बार में छत्तीसगढ़ के करीब 850 श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। इस विशेष ट्रेन का संचालन 5 मार्च से हो रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था है। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद है। आईआरसीटीसी से यह एमओयू 3 साल के लिए साइन किया गया है। इसे 2 साल बढ़ाया भी जा सकता है।

एसपी ने दो आरक्षकों को किया निलंबित, एक बर्खास्त

बिलासपुर। अनुशासनहीन आरक्षकों पर

कार्रवाई करते हुए एसपी ने 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं लंबे समय से अनुपस्थित आरक्षक देव कुमार जगत को बर्खास्त किया गया है। बता दें कि सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक नीलकमल सिंह राजपूत अपनी लक्जरी कार से देसी शराब की तस्करी करा रहा था। इसकी सूचना पर मोपका पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कार से 10 पेटी देसी शराब, खाकी वर्दी, एक प्लास्टिक केन, लाठी, खाकी रंग का बॉडीगार्ड कपड़ा, आरक्षक के नाम की बैंक पासबुक, उसका आईडी कार्ड जब्त किया गया है। वहीं इसकी भनक लगते ही आरक्षक नीलकमल राजपूत फरार हो गया है। इस मामले में एसपी ने आरक्षक नीलकमल को निलंबित कर दिया है। वहीं दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरक्षक सौरभ चौबे को भी निलंबित कर दिया गया है। आरक्षक नीलकमल की कार में पुलिस की वर्दी, एक प्लास्टिक का केन, एक प्लेट जिसमें पुलिस लिखा है, वहीं आरक्षक का बैंक खाता, चेकबुक, आरक्षक का आइकार्ड, डेबिट कार्ड, गैस कार्ड मिला है। इसके अलावा आरक्षक ने एक आवेदन एसपी के नाम पर लिखा था, जिसमें तखतपुर थाने से सकरी स्थानांतरित करने की बात लिखी है। पुलिस ने इस आवेदन को भी जब्त कर लिया है।

धान की अवैध खरीदी के मामले में सहायक समिति प्रबंधक और दो ऑपरेटर निलंबित

रायपुर। रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के बरगढ़ के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक शिवकुमार डनसेना, कम्प्यूटर आपरेटर भोलाराम जायसवाल, एवं कम्प्यूटर आपरेटर शेषकुमार जायसवाल को अवैध धान खरीदी की शिकायत सही पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। उप आयुक्त सहकारिता श्री चंद्रशेखर जायसवाल ने बताया कि उक्त तीनों के संबंध में यह शिकायत मिली थी कि इन्होंने षड्यंत्र कर अपने परिवार के सदस्यों के नाम फर्जी पंजीयन करने तथा मृत व्यक्तियों के नाम से भूमिहीन व्यक्तियों का फर्जी कृषक पंजीयन कर, फर्जी रूप से धान विक्रय कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई है। इस शिकायत की जांच में मामला सही पाए जाने पर उक्त तीनों कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है।

वसुंधरा सम्मान से सम्मानित होंगे डा. विश्वेश ठाकरे

रायपुर। कीर्तिशेष देवीप्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित और लोकजागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान इस वर्ष सुपरिचित पत्रकार-लेखक डा. विश्वेश ठाकरे को प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध की अध्यक्षता में गठित निर्णायक समिति के सदस्यों सर्वश्री, ईवी मुरली, देवेंद्र गोस्वामी, राजेंद्र सोनबोईर आलोक तिवारी, डा.रक्षा सिंह, श्वेता उपाध्याय, परविंदर सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वसुंधरा सम्मान के संयोजक विनोद मिश्र, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, स्वागत समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर, सचिव मुमताज ने इस निर्णय की जानकारी दी है, वसुंधरा सम्मान का यह निरंतर 24 वां आयोजन है, सम्मान समारोह स्व। देवी प्रसाद चौबे की 48 वीं पुण्य तिथि के अवसर पर बुधवार 14 अगस्त 2024 को दोपहर 3.30 बजे महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित किया जाएगा।

निर्णायक समिति ने अपने वक्तव्य में कहा है कि डा। विश्वेश ठाकरे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिनका राज्य की पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान है, वे विगत तीस वर्षों से पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, विश्वेश ठाकरे की प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में हुई है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय से बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल किया तथा जनसंचार में पीएचडी किया है, 1996 से 2008 तक रायपुर से प्रकाशित अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में रिपोर्टर तथा चीफ रिपोर्टर के रुप में कार्य कर चुके हैं। 2008 से लेकर 2018 तक रायपुर के अनेक टीवी चैनलों में विशेष संवाददाता के रुप में जनहित की अनेक खोजपरक खबरों का लेखन- संपादन किया है।

2018 से 2021 तक रायपुर के एक

प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक के रिजनल स्टेट एडिटर के रुप में वे रचनात्मक पत्रकारिता के प्रति समर्पित रहे हैं। वर्तमान में रायपुर में एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक के रूप में पत्रकारिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। डा. विश्वेश ठाकरे का एक कविता संग्रह- पंखों पर लिखी आयतें भी प्रकाशित हो चुका है। उन्हें पूर्व में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग अलंकरण, मीडिया विमर्श सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं। डॉ. विश्वेश ठाकरे छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारिता और साहित्य की मिली जुली परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से यह समारोह लोकजागरण की संस्था' वसुंधरा श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन भिलाई इस्पात संयंत्र आफिसर्स एसोशिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

विगत वर्षों में स्व. रमेश नैयर, स्व. श्याम लाल चतुर्वेदी, स्व. कुमार साहू, स्व. बसंत कुमार तिवारी, स्व. विनोद शंकर शुक्ल, स्व. शरद कोठरी, स्व. बबन प्रसाद मिश्र, डॉ. हिमांशु द्विवेदी, दिवाकर मुक्तिबोध, आशा शुक्ला, गिरिजाशंकर, ज्ञान अवस्थी, श्याम वेताल, अभय किशोर, डॉ. सुशील त्रिवेदी, गिरीश पंकज, बीकेएसरे, प्रकाश दुबे, स्व. तुषार कांति बोस, ईवी मुरली, सतीश जायसवाल, लीलाधर मंडलोई और सुधीर सक्सेना को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

कांग्रेस विधायक के पति और समर्थकों पर आदिवासी पत्रकार के अपहरण और मारपीट का आरोप

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरुर नगर में कांग्रेस विधायक के पति पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक आदिवासी पत्रकार के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपहरण कर विधायक कार्यालय ले जाने और जातिगत गालियां देकर बुरी तरह से पिटाई का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। यह मामला गुरुर थाना क्षेत्र का है।

बता दें कि संजारी बालोद कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा के पति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भाजपा महिला पार्षद की शिकायत पर गुरुर नगर की आठ लोगों के साथ पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के खिलाफ दर्ज धारा 333, 296, 115 (2), 351(2), 191(2), 3 (5) बीएनएस के तहत दर्ज मामला शांत भी नहीं हुआ था। अब एक पत्रकार की रिपोर्ट पर गुरुर पुलिस ने भैय्याराम सिन्हा सहित पांच लोगों पर धारा 191(2), 296, 115 (2), 351(2)(3), 140(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

घटना की शुरुआत 12 जुलाई को होती है, जब गुरुर नगर में प्रशासन ने 43 निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को अवैध करार देते हुए बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कांग्रेस की विधायिका संगीता सिन्हा, उनके पति पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा और स्थानीय व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे। यह मामला तनावपूर्ण हो गया, जब कुछ महिलाएं भाजपा महिला पार्षद कुंती सिन्हा के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने लगीं। इस घटना के बाद कुंती सिन्हा ने गुरुर

थाने में चार नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की शिकायत के बाद भी जब लगभग 1 सप्ताह बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो जिले के दौरे पर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आए। उनसे महिला पार्षद ने मामले की शिकायत की। जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने को लेकर डिप्टी सीएम के निर्देश पर गुरुर थाना टीआई को निलंबित कर दिया गया।

मामले की जांच शुरू होती ही भाजपा महिला पार्षद की शिकायत पर चार नामजद लोगों के खिलाफ धारा 333, 296, 115 (2), 351(2), 191(2), 3(5) बी एन एस। के तहत मामला दर्ज किया गया है और विवेचना के बाद पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के अलावा चार लोगों का नाम जोड़ मामले में आरोपी बनाया गया। जिसके बाद 26 जुलाई को थाना से नोटिस जारी कर 27 जुलाई को थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जहां भैय्याराम सिन्हा को नए कानून के अनुसार थाना में शपथ पत्र भरवा कर उन्हें छोड़ दिया गया।

मामले में अपने पति को आरोपी बनाए जाने के बाद विधायक संगीता सिन्हा 28 जुलाई को गुरूर थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ दर्ज शिकायत के विरोध में करीब 4 घंटे तक थाने में धरना दिया। और जब भाजपा महिला पार्षद को घर से घसीटकर सड़क पर पटका जा रहा था, तो बीच-बचाव करने आए पार्षद के दामाद को घसीटने वाली महिला ने पार्षद के दामाद के खिलाफ धक्का-मुक्की और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने दो दिन बाद शिकायत वापस लेने कोर्ट में अपना आवेदन भी पेश कर दिया है।

वहीं इस मामले की खबर शेयर करने पर स्थानीय पत्रकार विनोद नेताम का अपहरण किया गया और उनकी पिटाई की गई। पीड़ित विनोद नेताम ने बताया कि पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के लोग गुरुर नगर के होटल में जबरदस्ती कार में डालकर विधायक कार्यालय लेकर गए, जहां पहले से मौजूद पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा सहित उनके लोगों द्वारा मारपीट जातिगत गाली और जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने गुरुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दी है। मामले में गुरुर पुलिस ने विनोद नेताम की शिकायत पर पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा के अलावा 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पत्रकार की पत्नी ने भी थाने में एक लिखित आवेदन दिया कि पूर्व विधायक के दो लोग उनके घर पहुंचे और गाली गलौच, जातिगत गालियां भी दी है उसके समर्थन में रात 10 बजे तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग भी थाने में डटे रहे हैं। इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। इधर इस पूरे मामले के बाद विधयाक संगीता सिन्हा देर रात एसपी से मिलने कंट्रोल रूम पहुंची थीं। मामले में एडिशनल एसपी अशोक जोशी ने बताया कि विनोद नेताम के शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट में परिसीमन विवाद पर सुनवाई

■ **दोनों पक्षों ने दिए अपने तर्क**

बिलासपुर। बिलासपुर वार्ड परिसीमन मामले में निगम का तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसी विषय में दायर अन्य मामलों की एक साथ सुनवाई तय कर दी है। निगम की ओर से अधिवक्ता रणवीर मरहाज ने कहा कि बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात बदलने के कारण परिसीमन किया जा रहा है। साथ ही इस संदर्भ में राज्य शासन ने 29 जुलाई को अधिसूचना भी जारी कर दी है।

परिसीमन मामले में निगम के वकील ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहर के वार्डों से झुग्गियां हटाकर अन्य वार्डों में शिफ्ट की गईं हैं। इस प्रक्रिया में 2600 से ज्यादा परिवारों का वार्डों से विस्थापन और व्यवस्थापन हुआ है। जनसंख्या के लिहाज से यह संख्या हजारों में है। इससे वार्डों में जनसंख्या

अनुपात कम ज्यादा हुआ। इस कारण परिसीमन जरूरी है ताकि जनसंख्या अनुपात सही हो सके। साथ ही कल 29 जुलाई को राज्य शासन ने परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी है इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अन्य मामलों के साथ इस मामले की भी सुनवाई एक साथ रख दी है। अगले सप्ताह प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की संभावना है।

आपको बता दें कि बिलासपुर नगर निगम के परिसीमन के खिलाफ पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे और शहर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने अपने सर्कुलर में परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है। राज्य सरकार इसके पहले वर्ष 2014 और 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर चुकी है। जब आधार एक ही है तो इस बार फिर क्यों परिसीमन किया जा रहा है।

याचिका में ये भी कहा गया है कि वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। पुरानी जनगणना को आधार मानकर तीसरी बार परिसीमन कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जनता को परेशान कर रही है। परिसीमन से कुछ लाभ नहीं होगा।

डीआईजी का आदेश रेलवे ट्रैक में मौत के बाद डेथ बॉडी हटाएगी आरपीएफ?

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तमाम आरपीएफ अफसर डीआईजी के एक आदेश को लेकर इन दिनों थोड़े परेशान नजर आ रहे है। डीआईजी ने आदेश जारी किया है कि रेलवे ट्रैक में यदि कोई लाश मिलती है तो उसकी वीडियोग्राफी कर उसे हटाना है। हालांकि वीडियोग्राफी का जिक्र भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दिया गया है। उपरोक्त आदेश में आरपीएफ हटाएगी ऐसा तो जिक्र नहीं है, लेकिन आदेश में ये भी कही नहीं लिखा कि किससे हटवाना है। जबकि जीआरपी यदि डोम को बुलवाकर लाश हटाती है तो इसके एवज में रेलवे द्वारा स्वीकृत राशि दी जाती है। आरपीएफ के सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में अफसर इस बात को लेकर काफी फटकार लगाते है कि उन्हें किसी भी तरह ट्रेन डिटेन न हो इसलि रेलवे ट्रैक में पड़ी डेथ बॉडी को हटाना है। आरपीएफ सूत्रों का दावा है कि डेथ बॉडी हटाने को लेकर कई कानूनी दाव-पेच है। यही कारण है कि अब तक ऐसा होता था कि जब तक जीआरपी या लोकल पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती थी तब तक लाश को वहां से नहीं हटाया जाता था, लेकिन अब आदेश जारी कर आरपीएफ और रेलवे स्टॉफ को ही हटाने कह दिया गया है।

रेलवे पुलिस ने अवैध टिकट दलालों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 14 दलाल को दबोचे

रायपुर। रेलवे स्टेशनों में सावन महीने और त्यौहार सीजन को देखते हुए यात्रियों की भीड़ लगी है। इस बीच रायपुर, बिलासपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों में अवैध टिकट दलाली का मामला सामने आया है। इस पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। आरपीएफ ने अवैध टिकट दलालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 14 दलालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की ओर से रेलवे आरक्षण टिकट की मांग को देखते हुए अवैध टिकट दलालों के खिलाफ एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान को गोपनीय रखते हुए तीनों मंडलों (बिलासपुर, रायपुर और नागपुर) और साथ में अपराध गुप्तचर शाखाओं को स्पेशल टास्क दिया गया। तीनों मंडलों में एक साथ अलग-अलग शहरों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, ब्रजराजनगर, नागपुर, नैनपुर, कोरबा, भिलाई, अनुपपुर, शहडोल, अम्बिकापुर, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगावं, डोगंरगढ़ में अवैध टिकट दलालों के खिलाफ रेड की कार्रवाई की गई। इस दौरान 14 अवैध टिकट दलालों को गिरफ्तार कर रेलवे अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इन अवैध टिकट दलालों के कब्जे से तीन लाख आठ हजार 617 रुपये मूल्य के टिकटों की जब्ती की गई है। बता दें कि अवैध टिकट दलालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के द्वारा वर्ष 2024 माह जून तक कुल 144 अवैध टिकट दलालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 42 लाख 90 हजार 614 रुपये के मूल्य की टिकटों की जब्ती की जा चुकी है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी है ।

वितरण कंपनी के खिलाफ युवक कांग्रेस का प्रदर्शन

कोरबा। प्रदेश की लचर हो चुकी विद्युत वितरण व्यवस्था के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्तासीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली कटौती और अनाप शनाप दिए जा रहे बिल के खिलाफ प्रदेश संगठन के निर्देश पर युवक कांग्रेस ने तुलसीनगर स्थित बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव कर दिया। युवक कांग्रेसियों का कहना है,कि सरकार में वापसी करने के साथ ही भाजपा आम जनता को परेशान करना शुरु कर दिया है।

विद्युत वितरण व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सत्तासीन भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। बिजली कटौती,बढ़ी हुई बिजली की दर और अनाप शनाप दिए जा रहे बिजली बिल के खिलाफ युवक कांग्रेसियों ने हल्लाबोल प्रदर्शन किया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर युवक कांग्रेसी तुलसी नगर स्थित बिजली विभाग के

मुख्य कार्यालय पहुंचे और उसका घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

युवक कांग्रेसियों का आरोप है,कि भाजपा राज में आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। विभाग लगातार कई घंटो तक बिजली कटौती करता है। बिजली के दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है इतना ही नहीं अनाप शनाप बिजली बिल देकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है।

युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश पंकज में बताया की कांग्रेस सरकार के जाते और भाजपा सरकार के आते ही कानून व्यवस्था से लेकर बिजली व्यवस्था बद से बदतर हो गई है सभी की मनमानी चल रही है बिजली बिल अनाप-शनाप आ रहे हैं बिजली बिल का रीडिंग लेने कोई नहीं आ रहा है जिससे आम जनता काफी परेशान है वही हल्की सी आंधी तूफान आने पर बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है।

पार्षद रवि चंदेल ने बताया कि एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन के बाद युवक कांग्रेस ने अपनी मांगो का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा,और कहा,कि मांग पर जल्द विचार नहीं किया जाता,तो फिर से आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा।

हमास हो या हिजबुल्ला सभी के लिए इजरायल काफी?

अभिनय आकाश

एक मुल्क जो 1948 में बना। एक देश है जिसके लिए अंग्रेजी की पदबंद प्रॉमिस्ड लैंड का प्रयोग किया गया। यहूदियों का देश इजरायल। जिसका जिक्र करते हुए हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इजरायल का भारत के साथ सैन्य सहयोग, इजरायल का अरब के साथ विवाद, इजरायल का फिलिस्तीन के साथ संबंध। जैसे 32 दांतो के बीच जीभ रहती है वैसे ही अरब राष्ट्रों के बीच इजरायल है। वह दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा होने व इतने आक्रामक पड़ोसियों से घिरा होने के बावजूद अपनी शर्तों पर जी रहा है। प्रगति कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी कर रहा है। हमास के साथ अक्टूबर 2023 से युद्ध में उलझा देश, लेबनान में सक्रिय संगठन के हमले में 12 बच्चों की मौत के बाद हिजबुल्ला से भिड़ता इजरायल। नाटो के सदस्य तुर्किए को आंखे दिखाता और सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम भुगतने की धमकी देता इजरायल। इजरायल इन दिनों कई अलग-अलग मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है। इसके बावजूद इजरायली सेना सभी मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया की मौत से पूरी दुनिया हैरान है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया मारा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक घर में उसके बॉडीगार्ड के साथ उसकी हत्या की गई। हत्या के पीछे कौन है ये वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया ये सब अभी साफ नहीं हो पाया है। इसके साथ ही शक की ऊंगलियां इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ भी उठ रही है। मोसाद और इजरायल की सरकार ने ये साफ कहा था कि अपने दुश्मनों और हमास के तमाम कमांडरों को वो ढेर करेगा। इस्माइल हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ थे। रात के 2 बजे जिस बिल्डिंग पर वो रह रहे थे, उस पर हवाई हमला हुआ। उसमें उनकी मौत हो गई। ऐसे में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि क्या इसके बाद हमास खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें कि हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया जरूर थे लेकिन वो बाहर रह रहे थे। वो पॉलिटिकल, मिलिट्री सपोर्ट जुटाने का काम करते थे। गाजा में हमास को चलाने वाले नेता का नाम याह्या सिनवार है। वहीं हमास के मिलिट्री विंग के लीडर का नाम मोहम्मद दाइफ है। ईरान के लिए ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि उसकी धरती पर अटैक हुआ है। आपको याद होगा कि जब सीरिया में ईरान के कॉसुलेट पर अटैक हुआ था। इस ड्रोन अटैक में सात कमांडर मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लिया था। उसने मिसाइलें दागी थी। उसका इफेक्ट कितना रहा ये चर्चा का विषय है। लेकिन पहली बार ईरान की तरफ से सांकेतिक ही सही इजरायल की टेरिटरी पर सीधा हमला किया था। इस बार तो ईरान की धरती पर ये घटना हुआ है। ऐसे में अगर ये बात सामने आती है कि इसमें इजरायल का हाथ है। फिर वो पलटवार जरूर करेगा। ये भी इसलिए जरूरी है कि एक मैसेज देना होगा कि हम भी इस इलाके में बड़ी शक्ति हैं। ईरान अगर हमला करता है तो इस पर कोई जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ से होती है तो तनाव और बढ़ जाएगा। इजरायल दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ हमास के साथ वो अक्टूबर 2023 से भिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ लेबनान में भी हिजबुल्ला के साथ उसकी भिड़ंत हो रही है। हिजबुल्ला को भी ईरान का सपोर्ट है। पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्ला के साथ भी उसकी खटपट की खबर सामने आ रही है। 1967 में सीरिया से कब्जा किए गए इलाके गोलन हाइट्स में मजद-अल-शम्स पर एक रॉकेट हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों क मौत हो गई थी। इजरायल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ है उसमें उन बच्चों की मौत हुई है, जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इजरायल ने आरोप लगाया कि इसे हिजबुल्ला ने अंजाम दिया। लेकिन हिजबुल्ला ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। लेकिन हिजबुल्ला इस तरह के हमले करता रहा है।

राहुल की विभाजनकारी राजनीति

ललित गर्ग

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी जिस तरह की बातें कह एवं कर रहे हैं, निश्चित ही यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रहा है, वे लगातार विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहन देते हुए भूल जाते हैं कि उनके ऊपर देश को तोड़ने नहीं, जोड़ने की जिम्मेदारी है। प्रश्न है कि कब राहुल गांधी इस महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए उसके साथ न्याय करेंगे? वे जानते नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उससे क्या नफा-नुकसान हो रहा है या हो सकता है। वे तो इसलिए बोल रहे हैं कि वे बोल सकते हैं, उन्हें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने महाभारतकालीन चक्रव्यूह और पद्म व्यूह का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना चाहा है। जिस तरह से उन्होंने बजट पूर्व हलवा परम्परा में वित्तमंत्री के साथ खड़े लोगों को जाति आधारित संरचना बताया वह कहीं से भी तार्किक नहीं लगता। इस सेरेमनी में तो उस वक्त मंत्रालय के जो सीनियर अफ़सर होते हैं, वे ही मौजूद रहते हैं। इसमें जातिवाद कहाँ से आया? यह बात समझ से परे है। यही वजह है कि हलवा परम्परा की जब राहुल गांधी अपनी तरह से विवेचना कर रहे थे, तब वित्त मंत्री ने माथा पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने जो तुलनाएँ की, वे निश्चित रूप से अतिरेक या अतिशयोक्ति कही जा सकती हैं। हर दिखते समर्पण की पीठ पर स्वार्थ चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार हर अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं स्वार्थ की राजनीति है, सत्तापक्ष को नुकसान पहुंचाने की ओछी मनोवृत्ति है।

लोकसभा में आम बजट पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना पुराना आरोप नए सिरे से दोहराया कि बजट बनाने वालों में कोई एससी-एसटी और ओबीसी अधिकारी नहीं होता, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वह समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति पर अड़े हैं। इस तरह की बेतुकी बातें करते हुए वे क्यों नहीं समझना चाहते कि ऐसी स्थिति और इस तरह की परम्परा कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के समय से ही चली आ रही है। कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन वह कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। राहुल गांधी एक तरह से यह कहना चाह रहे हैं कि अनारक्षित वर्गों के अधिकारी आरक्षित वर्गों के हितों की उपेक्षा करते हैं। इस तरह वे देश की परम्पराओं एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समझे बिना ऐसा कुछ कह जाते है जो देश की एकता, अखण्डता एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत होता है। राहुल के बोलने का बचकानापन तो कभी-कभी सारी हदें पार कर जाता है। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया हैं कि उच्च जाति के शिक्षक प्रश्नपत्र बनाते हैं, इसलिए आरक्षित वर्ग के छात्र फेल हो जाते हैं। आखिर यह भड़काऊ राजनीति नहीं तो और क्या है?

राहुल गांधी ने बजट पर सरकार को घेरने के लिए महाभारतकालीन घटनाओं का उल्लेख करते हुए यह भी कह डाला कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, उसी तरह देश को भी मोदी सरकार ने घेर रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत जिन छह लोगों को इस घेराबंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया, उसमें अंबानी-अदाणी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी शामिल कर लिया। उन्होंने दावा किया है कि भारत पर कब्जा करने वाले चक्रव्यूह के पीछे तीन ताकतें है- पहली एकाधिकार पूंजी का विचार, जिसमें दो लोगों को देश की समूची संपत्ति का मालिक बनने की अनुमति देना। दूसरा देश की संस्थाएं, एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग हैं एवं तीसरी राजनीतिक कार्यप्रणाली है। इन तीनों ने मिलकर देश को तबाह कर दिया है। इस तरह के बयानों एवं बोलों से स्पष्ट है कि वह मनमाने और बेतुके तर्क देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। वह अपनी ऐसी बातों से चर्चा में तो आ जाते हैं और उनके समर्थक उनकी वाह-वाही करने में भी जुट जाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह न तो समाज को कोई सही दिशा दे पा रहे हैं और न ही सरकार को कोई सार्थक सुझाव। यह स्थिति देश के लिये नुकसानदायी है, चिन्तनीय है।

राहुल गांधी के रुख-रवैये एवं अतिश्योक्तिपूर्ण तर्कों से यही लगता है कि वह अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं। अपनी चुनाव पूर्व की आक्रामकता से वे उपरत नहीं हो पाये हैं। वे सदन के भीतर एवं सदन के बाहर ऐसी ही तर्कहीन बातों एवं बयानों से अराजक माहौल बना रहे हैं। आखिर वह जो कुछ मोदी सरकार से चाह रहे हैं, उसे कांग्रेस संगठन और साथ ही अपने दल द्वारा शासित राज्य सरकारों में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा है? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में बजट बनाने में आरक्षित वर्गों के कितने अधिकारियों की हिस्सेदारी होती है? वह मोदी शासन की तरह मीडिया में भी आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी कई बार उठा चुके हैं, लेकिन यह देखने को तैयार नहीं कि आखिर उनके परिवार के प्रभुत्व वाले मीडिया संस्थान में इन वर्गों के कितने लोगों की हिस्सेदारी है?

लोकसभा की कार्रवाई कांग्रेसी एवं विपक्षी सांसदों के वाक आउट, हंगामे, अनर्गल बहस की भेंट चढ़ रही है। विपक्षी अपनी सार्थक भूमिका का निवर्हन करने की बजाय लगातार सत्तापक्ष को घेरने एवं आरोप-प्रत्यारोप की घटिया राजनीति में लगा है। जिससे सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देश भी इन त्रासद घटनाओं से कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है। आखिर सरकार करे, तो क्या करे? उसने हर सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठकें करके देख ली। दोनों सदनों के अध्यक्ष और उप-सभापति ने बारंबार समझा-समझाकर सहयोग की अपील कर ली। प्रधानमंत्री ने भी बार-बार सदस्यों से सदन को शांतिपूर्वक बहस के जरिये चलने-चलाने की विनम्र अपील कर डाली। बावजूद इसके एनडीए को सत्ता के आरंभ 2014 से अभी तक विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पाया है। संसद के सत्रों की ही भांति नीति आयोग की बैठक का भी लगभग सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आईं जरूर, लेकिन उन्होंने भी यह आरोप लगाकर बाहर का रास्ता नापा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। हालांकि, सरकार ने इससे इनकार किया है। क्या देश के मतदाताओं ने भारी संख्या में विपक्ष को इसीलिए भेजा है कि वे उनके हितकारी कार्यों पर संसद में बहस करने के बजाय सब कुछ हंगामे या बहिष्कार की भेंट चढ़ा दें? कब विपक्ष संसद में मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप उनको सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति गंभीर होकर अपनी दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करते हुए देश-निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करेंगे?

नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं, जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी, इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपाय और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों एवं विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को राजनीति करने की क्यों सूझी? वे यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी, यहां तक की राष्ट्रीय हित के विषय पर भी सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में तो लगातार मिल रही है, लेकिन नीति आयोग में भी वैसी ही नकारात्मक स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया, क्योंकि बजट में विपक्ष-शासित राज्यों की कथित तौर पर अनदेखी की गई। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है, और यदि ऐसा लगता है, तो उन्होंने अपनी बात आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर गंवना क्यों पसंद किया?

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-7)

गतांक से आगे...

पीछे कहा गया है कि ब्रह्म से ब्रह्माण्ड पर्यन्त तक की समस्त प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से निरूपण करना ही पुराणों का विषय है। सो सर्वप्रथम यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्माण्ड का रचयिता कौन है! इस प्रश्न का समाधान करने को पहिला ब्रह्मपुराण उपस्थित होता है जिससे यह सूचितं किया गया है कि ब्रह्म ब्रह्माभवत्स्वयम (तैत्तिरीय- 3।12।6।3) के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्मा रूप से सृष्टि का रचयिता है। यहीं तत्त्व समझाने के लिए पहिले पुराण का नाम ब्रह्म रखा गया है।

स्वभावत: दूसरी जिज्ञासा होगी कि ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा हुये ? इसका उत्तर देने के लिये दूसरा पद्मपुराण उपस्थित है, अर्थात् - ब्रह्मा जी पद्म (नाभि-कमल) से पैदा हुये हैं।

पद्म वहां से निकला! इस प्रश्न की पूति तीसरा विष्णुपुराण करता है। यहाँ तक सर्वाधार विष्णु से कमल और कमल से ब्रह्मा, इन तत्त्वों को विलोम क्रम से प्रकट किया है।

अब जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मा जी ने मूल सृष्टि का पता कैसे लगाया ? तब चौथा शिवपुराण जवाब देता है कि शिव अर्थात् - वेद से। पौराणिक भाषा में शिव नाम वेद का हे जैसा कि पद्मपुराणोक्त श्रीमद्भागवत-माहात्म्य (1।16) के अट्टशूला जनपदा: शिवशूला द्विजातय: आदि श्लोक की व्याख्या करते हुए- शिवो वेद: ऐसा लिखा है। वस्तुत: यथापूर्वमकल्पयत सिद्धान्त के अनुसार वेद ही सृष्टि रहस्य का अपूर्व खजाना है।

लीन अर्थ के गमक चिन्हों को लिङ्ग कहते हैं। गहाप्रलय में विलीन हुए पदार्थों के कारणात्मक तत्त्वों को पुन: संधीभूत करना ही सर्ग है- यह रहस्य पांचवें लिङ्ग-पुराण से प्रकट होता है।

क्रमश: ...

बाल गंगाधर तिलक

बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतन्त्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के आरम्भिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के लिये नये विचार रखे और अनेक प्रयत्न किये। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशान्ति के पिता कहते थे।

लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अन्त:करण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बिपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष और वी. ओ. चिदम्बरम पिल्लै आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिये निकट सहयोग किया। तिलक को कई कारणों से जातिवादी व स्त्री शिक्षा का विरोधी भी देखा जा सकता है।

लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गाँव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कालेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कालेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसायटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे।[3]

लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गयी। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चन्द्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल-बाल-पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रान्तिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रान्तिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया जिसकी वजह से उन्हें बर्मा (अब म्यांमार) स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गये और 1916 में एनी बेसेंट जी और मुहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल लीग की स्थापना की।

सन 1919 ई. में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिये स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गये थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधायी परिषद) के चुनाव के बहिष्कार की गान्धी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिये प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नये सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त,1920 ई. को बम्बई में उनकी मृत्यु हो गयी। मरणोपरान्त श्रद्धाञ्जलि देते हुए गान्धी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रान्ति का जनक बतलाया।

अग्निपथ योजना पर विपक्ष फैला रहा अफवाह!

मृत्युंजय दीक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर द्रास क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि अग्निपथ योजना फिलहाल बंद नहीं होने जा रही है। इसी के साथ इस अवसर पर भाजपा शासित राज्यों ने अग्निवीरों को आरक्षरण की घोषणा करके विपक्ष के विरोध की धार को कुंद करने का प्रयास किया। लोकसभा चुनावों में अग्निपथ योजना को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर सिमट जाने पर अब विपक्ष अग्निपथ योजना पर अपने को सही सिद्ध मान रहा है और उसके नेता यत्र तत्र इंडी सरकार आने पर इस योजना को समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निपथ योजना की प्रमुखता से चर्चा की।

अग्निपथ योजना का विरोध राजग गठबंधन में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) ने भी किया है और इसमें संशोधन करने की मांग कर रखी है। स्मरणीय है कि इस योजना की घोषणा के बाद बिहार में ही सबसे अधिक उपद्रव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी आरोपों व उनके द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखना है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के उन दावों को भी खंडन किया कि पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना प्रारम्भ की गई है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी विरोधी दल सत्य को अंगीकार करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नये नवेले अति उत्साही सांसद अवधेश प्रसाद व अन्य दलों के नेताओ ने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तब अग्निपथ योजना को 24 घंटे में बंद कर दिया जायेगा।

उधर प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, असम और अरुणांचल प्रदेश आदि राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देकर युवाओं को बेहद आकर्षक उपहार दिया है और उनके मन से यह डर दूर करने का प्रयास किया है कि सेना में चार साल की सेवा के बाद उनका क्या होगा। विपक्षी दल यही डर दिखाकर भ्रम फैलाते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। मंत्रालय ने बीएसएफ और सीआईएसएफ में भी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने सहित ऊपरी आयु सीमा में पांच साल और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट देने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। अग्निपथ योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए सरकार के पास अभी अन्य अवसर भी हैं जिनकी घोषणा समय आने पर की जाएगी।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की थी जिसके अंतर्गत थल, जल और वायु सेना में 4 वर्ष के लिए युवाओं को भर्ती किया जाता है जिसमें छह महीने का प्रशिक्षण भी शामिल है। 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों की रेटिंग तैयार की जायेगी इसी रेटिंग लिस्ट को मानक मानकर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष तक के युवक और युवतियां अपना आवेदन कर सकते हैं।अग्निपथ योजना में भर्ती होने के लिए कक्षा 10 व 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।अग्निपथ योजना की अनेक विशेषताएं है। इस योजना में योग्यता व समानता के आधार पर ही भर्ती होगी। सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीरों को उनके कौशल के अनुरूप स्किल प्रमाणपत्र दिया जायेगा जिसके आधार पर वह अपना व्यवसाय कर सकते हैं अथवा नौकरी करने जायेंगे तो उस कौशल के लिए प्रशिक्षित होंगे। सेवा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होने की अवस्था में अग्निवीरों का बीमा भी किया जा रहा है।

विरोधी दल यह अफवाह भी फैला रहे हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत बलिदान होने वाले जवानों को पुरस्कृत नहीं किया जायेगा जबकि वास्तविकता यह है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत बलिदान होने वाले जवानों को भी पुरस्कार दिये जायेंगे। योजना के अंतर्गत अग्निवीरों का आरंभिक वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह है जो चौथे साल तक बढ़कर 40,000 तक हो जायेगा। सेवा समाप्ति के चार साल बाद सैनिकों को 10 से 12 लाख रुपये तक दिये जायेंगे जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे। विपक्ष यह आरोप भी लगा रहा है कि मात्र छह माह के प्रशिक्षण में ही अग्निवीर कैसे प्रशिक्षित हो सकेगा और देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकेगा, यह आरोप भी पूरी तरह से भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। अग्निवीर भी अन्य सैनिकों की तरह ही प्रशिक्षित किया जायेगा।

विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने यह योजना सेना के साथ बिना किसी विचार -विमर्ष के लागू कर दी है यह आरोप भी पूरी तरह से झूठ है। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार के समय कारगिल युद्ध हुआ तभी सेना की औसत आयु कम करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी और सेना के कमांडरों की बैठक में इस योजना पर व्यापक विचार विमर्ष हुआ था। वर्तमान रक्षा मंत्री ने इस विषय पर विभिन्न हितधारकों के साथ हुई लम्बी और तथ्य परक बैठकों के विषय में सदन में विस्तृत जानकारी दी है। अग्निवीर जैसी योजनाएं इजराइयल सहित कई देशों में लागू हैं। आज भारत के समस्त विरोधी दल अग्निपथ योजना का विरोध सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत ही कर रहे हैं। इस योजना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी सेना व सैनिकों का साथ नहीं दिया है। वो लोग अग्निपथ योजना का उपहास उड़ा रहे हैं जो सेना एयरस्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व दिवंगत थलसेना प्रमुख विपिन चन्द्र रावत को गली का गुंडा कहा था।यह वही लोग हैं जिनके कारण सेना के जवानों के पास बुलेटप्रूफ जैकेट व जूते तक नहीं होते थे किंतु अब जब हमारी सेना हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं जिनके हाथ बड़े- बड़े रक्षा घोटालों से सने हुए हैं। वो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं जिनको कारगिल विजय दिवस की उपलब्धि महत्वहीन लगती है। यह वही लोग हैं जिन्होंने 2004 से 2014 तक कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं। वो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में सीमा पर आतंकवाद का शिकार सैनिकों के क्षत विक्षत शवों पर कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की जाती थी। वास्तव में इन दलों को डर सता रहा है कि अगर यह योजना सफल हो गई तो बेरोजगारी का मुद्दा उनके हाथ से निकल जायेगा।अनुशासित युवा, सशक्त युवा और प्रशिक्षित युवा इन नेताओ के कहने से चक्का जाम करने नहीं आएगा।

अग्निपथ योजना भारत की सेना व भारत के युवा दोनों के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। इससे एक ओर युवाओं के लिए नये अवसर खुल रहे हैं दूसरी ओर आतकंवाद के खतरनाक दौर में देश को अतिरिक्त सैनिक मिल रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरुद्ध विपक्ष उसी प्रकार विरोध की मुहिम चला रहा है जिस प्रकार कोविड वैक्सीन के विरुद्ध चलाई थी। केंद्र व राज्य सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देकर एक बहुत बड़ा उपहार दिया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान सरकार अग्निवीरों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी।

मात्र मोदी विरोध के लिए अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि संतानी भारतीय भारत की धरती को अपनी माँ से भी उच्च स्थान देते हुए इसे भारत माँ कहते हैं और भारत की सेना का हिस्सा बनना केवल एक नौकरी मात्र नहीं अपितु देश व समाज की सेवा करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। सेना से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी सैनिकों में मन में देश सेवा करने के लिए अप्रतिम स्थान होता है।

आज का इतिहास

1946 संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गयी।
1960 पाकिस्तान की पुरानी राजधानी को कराची से बदलकर इस्लामाबाद में तबदील कर दिया गया।
1965 ब्रिटिश टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापन प्रतिबंधित किया गया।
1971 अंतरिक्ष यात्री जेम्स इरविन और डेविड स्कॉटकेम चंद्र रोवर पर चंद्रमा सफारी के दौरान जेनेसिस रॉक नामक चट्टान के पार। यह लगभग 4,500 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है।
1976 सिएटल सीहॉक्स ने अपना पहला फुटबॉल गेम खेला।
1984 वाणिज्यिक पीट-कटर ने उत्तरी पश्चिम इंग्लैंड के चेशायर के लिंडो मॉस में अमन के संरक्षित दलदल की खोज की, जिसे लिंडो मैन कहा जाता है।
1995 शनि के एक और चन्द्रमा की खोज हब्बल दूरबीन द्वारा की गयी।
1997 स्टीव जॉब्स ने बोस्टन शहर के मैकवर्ल्ड, एप्पल कंप्यूटर और इंक से दोबारा जुड़े।
1997 द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित सामग्री के अनुसार, 1950 के दशक के दौरान परमाणु परीक्षण थायराइड कैंसर का मूल कारण हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप 10,000 से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है, जो कि थायरॉइड कैंसर का विकास कर सकते हैं।
2000 ईरान में पहली बार महिलाओ को भी मदरसों में इमाम बनाने का अधिकार दिया।
2000 न्यायाधीश जे। कैल्विट क्लार्क जूनियर ने अपनी एकजुटता पर फैसला सुनाया कि आर। एम। यूट्स। टाइटैनिक कंपनी, जिसके टाइटैनिक पर वसूली के दावे थे, को डूबते हुए जहाज में काटने और कलाकृतियों को लूटने से मना किया गया था।
2001 मानव क्लोनिंग पर प्रतिबंध कानून में मतदान नहीं है, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने इसके लिए मतदान किया क्योंकि डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली सीनेट इसके प्रति विरोधी थी।
2005 सऊदी अरब के बादशाह फहद बिन अब्दुल अजीज का निधन हुआ और दिवंगत बादशाह के भाई शाहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को देश का नया शासक नियुक्त किया गया।
2006 यूनाइटेड किंगडम और कैलिफोर्निया राज्य पर्यावरण पर उनके प्रभावों को कम करने के लिए मेल खाते हैं। प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर और गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच की यात्रा के बाद इस समझौते पर आए।
2007 न्यूज़ीलैंड ने पहली बार आसानी से उपलब्ध जैव-ईंधन काउंटर पर इसे लॉन्च किया, जो 90 प्रतिशत ईंधन के साथ-साथ गायों के दूध से उत्पादित दस प्रतिशत जैव-इथेनॉल से बना है।

हिजबुल्ला का हमला या आयरन डोम की खराबी?

अभिनय आकाश

करीब 9 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रही इजरायल-हमास की जंग के बीच अचानक से एक नई जंग की आशंका बड़ी तेजी से बढ़ गई है। इजरायल और उसके उत्तरी सीमा के पड़ोसी मुल्क यानी लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला के बीच अब बड़ी जंग की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल, हुआ ये है कि इजरायल के कब्जे वाली गुहान पहाड़ियों पर एक जोरदार हमला हुआ है। ये हमला फुटबॉल के मैदान पर हुआ है जिसमें कम से कम 12 बच्चे और किशोरों की मौत हो गई है। इजरायल ने इस हमले का आरोप हिजबुल्ला पर लगाया है जबकि हिजबुल्ला ने इस हमले से इनकार किया है। इस हमले ने इजरायल के साथ-साथ अमेरिका को भी एक्शन मोड में ला दिया है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने अमेरिकी दौरे को अधूरा छोड़कर लौट आए हैं और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि फुटबॉल ग्राउंड पर हुए अटैक के बाद ऑल आउट जंग की सूरत क्यों बन रही है। गोलन हाइट्स को लेकर मचे बवाल का बैकग्राउंड क्या है। दुनियाभर के नेताओं की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं।

आज की रात हिजबुल्ला के लिए कयामत की रात साबित हो सकती हैं। इजरायल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ है उसमें उन बच्चों की मौत हुई है, जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। इजरायल लौटते ही नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। नेतन्याहू ने मजद-अल-शम्स के बदले का आदेश दे दिया है। अब लेबनान पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी इजरायली डिफेंस फोर्स कर रहा है। आईडीएफ ने अपने छह एयरबेस को हमले के लिए एक्टिव भी कर दिया है। इजरायल के 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं।

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि ये हमला हिजबुल्ला ने नहीं किया है। इजरायल के ही एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की एक नाकाम मिसाइल ने अपने ही फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक कर दिया। इजरायल के पास इस वक्त आयरन डोम की दस बैट्रीज हैं। हर बैट्रीज में चार लॉन्चर है, जो रडार से जुड़े होते हैं। ये रडार आने वाली हमलावर मिसाइल को डिटेक्ट करता है और लॉन्चर से उस मिसाइल को ऑटोमैटिकली इंगेज कर हवा में ही मार गिराने के लिए एक मिसाइल लॉन्च हो जाती है। दावा किया गया है कि ऐसी ही एक मिसाइल गलती से टारगेट पर न जाकर फुटबॉल के मैदान पर हमला कर बैठी। अब इजरायल इसका ठीकरा हिजबुल्ला के सिर पर फोड़ रहा है। अल अरबी चैनल जो हमेशा इजरायल के विरोध की बात कहता है उसकी एक पत्रकार ने दावा किया कि एक एंबुलेंस ड्राइवर ने किसी अन्य शख्स से सुना है कि गिरने वाली मिसाइल आयरन डोम की थी।

गोलान हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में

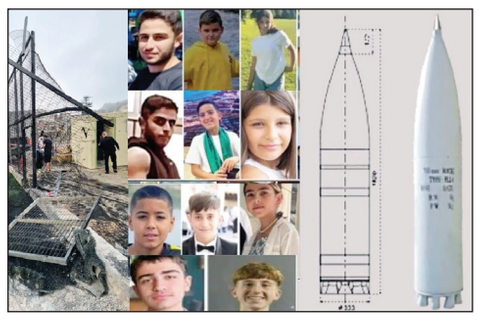

एक चट्टानी पठार है, जो राजधानी दमिश्क से लगभग 60 किमी दूर है। पानी से समृद्ध, गोलान हाइट्स उत्तरी इज़राइल के गैलील क्षेत्र और गैलील सागर पर नज़र रखती है और सीरियाई-नियंत्रित हिस्से पर दमिश्क के मार्ग पर हावी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलान हाइट्स जॉर्डन और लेबनान के साथ सीमा साझा करती है। अरबी में जौलान के रूप में भी जाना जाता है।

इजरायल ने 1967 के मिडिल ईस्ट युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। उसने अपनी पहली बस्ती वेस्ट बैंक में नहीं, बल्कि गोलन हाइट्स में ही बनाई थी और 1981 में इस पर कब्जा कर लिया था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे मान्यता नहीं दी है। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसे इस्राइली क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। यहां कुछ डूज लोगों के पास इस्राइली नागरिकता है। कई लोगों के मन में अभी भी सीरिया के प्रति सहानुभूति है और इस्राइल के कब्जे को खारिज कर दिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस्राइली समाज के साथ संबंध बढ़े हैं। हालाँकि, 2019 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वाशिंगटन गोलान हाइट्स पर इज़राइल की संप्रभुता को मान्यता देगा - एक ऐसा कदम जिसने वर्षों की नीति को पलट दिया और सीरिया के साथ तनाव बिगड़ गया

आज की तारीख में गोलान हाइट्स में लगभग 40,000 लोग रहते हैं, जिनमें से आधे से अधिक ड्रुज़ अरब हैं। लेकिन वास्तव में ड्रुज़ कौन है? ड्रुज़ अरब एक अद्वितीय धार्मिक और जातीय समूह हैं। उनकी परंपरा 11वीं शताब्दी से चली आ रही है और इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म और यहां तक ??कि शास्त्रीय यूनानी दर्शन के तत्व भी शामिल हैं। वे न तो धर्म में परिवर्तन की अनुमति देते हैं और न ही अंतर्विवाह की। ड्रुज़ दशकों से बशर अल-असद और उनके पिता हाफ़िज़ अल-असद के शासन के प्रति वफादार रहे हैं। जब इज़राइल ने गोलान पर कब्जा कर लिया, तो ड्रुज़ को नागरिकता का विकल्प दिया गया, लेकिन अधिकांश ने इसे अस्वीकार कर दिया और अभी भी खुद को सीरियाई के रूप में पहचानते हैं। वर्तमान में 20,000 से अधिक ड्रुज़ गोलान हाइट्स में रहते हैं और 30 से अधिक बस्तियों में फैले लगभग 25,000 यहूदी इजरायलियों के साथ भूमि साझा करते हैं। 2023 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2027 तक वहां अपनी आबादी को दोगुना करने की इज़राइल की योजना पर चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब क्षेत्र में भूमि और पानी की बात आती है तो गोलान में ड्रुज़ को इजरायलियों द्वारा भेदभावपूर्ण नीतियों का सामना करना पड़ता है। ड्रुज़ नेताओं ने यह भी बताया कि क्षेत्र में उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है। शायद यही कारण है कि इज़राइली मीडिया इज़राइल में नागरिकता चाहने वाले डूज़ की संख्या में वृद्धि दिखाता है।

इसका सीधा सा जवाब है- सुरक्षा. गोलान हाइट्स की ऊँचाई इज़राइल को सीरिया में गहराई तक अवलोकन बिंदु प्रदान करती है - एक ऐसा देश जिसके साथ इज़राइल के तनावपूर्ण संबंध हैं। इज़राइल का यह भी कहना है कि गोलान को बनाए रखने से इज़राइली कस्बों और दमिश्क के बीच एक बफर जोन बनाने में मदद मिलती है। तेल अवीव ने यह भी कहा है कि उसे डर है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद का सहयोगी ईरान, इज़राइल पर हमले शुरू करने के लिए सीरियाई सीमा पर स्थायी रूप से खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 1974 के युद्धविराम समझौते के बाद, 400 वर्ग किमी का एक असैन्यीकृत बफर ज़ोन भी है जिसमें कोई भी पक्ष प्रवेश नहीं कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र डिसइंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स (यूएनडीओएफ) और संयुक्त राष्ट्र ट्रूस पर्यवेक्षण संगठन (यूएनटीएसओ) के पास क्षेत्र में शिविर और चौकियां हैं। गोलान हाइट्स बनयास जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों का भी घर है, जो जॉर्डन नदी को पानी देते हैं। शुष्क क्षेत्र में पानी एक प्रमुख संसाधन है। इसके अलावा, गोलान इज़राइल का एकमात्र स्की रिसॉर्ट भी है।

इजरायल के नियंत्रण वाले गोलन हाइट्स के मजदल शम्स के डूज शहर में एक फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले में 12 बच्चों और किशोरों की मौत हो गई। हमले के वक्त बच्चे मैदान में खेल रहे थे। हमले से पहले सायरन तो बजा लेकिन भागने का वक्त नहीं मिल पाया। हेलिकॉप्टर और एंबुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस्त्राइल ने इस हमले के लिए हिज्बुल्लाह को दोषी ठहराया, लेकिन हिज्बुल्लाह ने इसमें किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया।

अमेरिका की यात्रा पर गए नेतन्याहू पहले ही देश लौट आए और आते ही सुरक्षा कैबिनेट की बैठक ली। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि हिज्बुल्लाह को इस हमले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उसने अब तक नहीं चुकाई है। इस्त्राइली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने इसे 7 अक्टूबर के हमास वाले हमले के बाद से सबसे घातक हमला बताया। उन्होंने कहा 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। विदेश मंत्री इस्त्राइल काट्ज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। हमारा जवाब इसे दिखाएगा। हम उस पल के करीब है जब हम एक पूर्ण युद्ध का सामना करेंगे। सरकार के धुर दक्षिणपंथी सदस्यों ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया का आह्वान किया। इमरजेंसी सर्विस के एक डॉक्टर ने कहा, हम मैदान पर पहुंचे और जलती हुई चीजें देखीं। हताहत लोग जमीन पर पड़े थे।

अभी क्यों उठी चीन से रिश्ते सुधारने की बात

चंद्रभूषण

भारत-चीन आर्थिक संबंध किसी निश्चित रास्ते पर चलने का नाम ही नहीं ले रहे। 2020 में गलवान घाटी के टकराव के बाद भारत में चीन की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वहां से होने वाले आयात को सीमित करने के प्रयास किए गए थे। साथ ही, चीन के पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने के लिए 2021 में जारी एक शासनादेश के मुताबिक भारत की जमीनी सीमाओं से लगे सभी देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकार के स्तर पर मंजूरी लेना जरूरी बना दिया गया था। सरकार का यह मूड देखकर चीनी ब्रैंड की कुछ मोबाइल फोन कंपनियों में हड़तालें हुई थीं और दो-एक जगह उनके ठिकानों पर तोड़फोड़ भी हुई थी। लेकिन अभी, केंद्रीय बजट से ठीक पहले आए इकॉनमिक सर्वे में चीन से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत से चीन के कूटनीतिक रिश्ते अभी फ्रिज में ही पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पद संभालने पर भी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ओर से बधाई संदेश नहीं आया। हफ्ते भर बाद आधिकारिक बधाई संदेश आया भी तो उस पर चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग का नाम लिखा था। ऐसे माहौल में चीन से एफडीआई बढ़ाने के सारे जतन करने का यह सर्वे वाला सुझाव कुछ अटपटा-सा है। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने जो सफाई इस प्रस्ताव के बारे में दी है, उसके मुताबिक दुनिया के आर्थिक-वाणिज्यिक वातावरण को देखते हुए भारत के सामने दो ही विकल्प बचते हैं। या तो चीन से बना-बनाया सामान मंगाकर अपने यहां सिर्फ उसकी पैकेजिंग और ब्रैंडिंग करके पश्चिमी बाजारों में बेचा जाए, या फिर चीनी पूंजी और तकनीक का आयात किया जाए। इसका मतलब कि उन्हें अपने यहां सीधे या किसी भारतीय भागीदार से सहयोग बनाकर फैक्ट्री लगाने दी जाए और अपने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हुए बेहतर मुनाफे के साथ चीजों को अमेरिका और यूरोप के बाजारों में उतारा जाए। हर हाल में चीन पर ऐसी निर्भरता क्यों? इस सवाल का जवाब देते हुए नागेश्वरन ने ग्रीन एनर्जी, टर्बाइनों, न्यूक्लियर टेक्नॉलजी और बैट्री वाली गाड़ियों जैसे कुछ खास क्षेत्रों में चीन की तकनीकी दक्षता और कुछ खास खनिजों, सिंथेटिक पदार्थों और रसायनों में उसके एकाधिकार का जिक्र किया। ज्यादा तह में जाएं तो असल बात कुछ मामलों में यूक्रेन युद्ध से पहले ही, लेकिन खास तौर पर यह लड़ाई शुरू होने के बाद यूरोपीय संघ, अमेरिका और कनाडा के रवैये से जुड़ी लगती है, जो अपने यहां चीन से होने वाले आयात को कम से कम रखना चाहते हैं। उनके यहां चीन से आने वाली चीजों में कुछ अपने सस्तेपन की वजह से खरीदी जाती हैं और कुछ तकनीकी श्रेष्ठता की वजह से। पश्चिमी मुल्क इस मामले में तितरफा रणनीति पर अमल कर रहे हैं। एक तो चीन की तकनीकी प्रगति की रफ्तार कम करना, जिसके लिए श्रेष्ठतम श्रेणी की माइक्रोचिप बनाने की सारी संभावनाएं उन्होंने अपनी तरफ से इस मुल्क के लिए बिल्कुल ठप कर दी हैं। दूसरा, श्रेष्ठ तकनीकी दक्षता वाली चीनी वस्तुओं के आयात को जांच-पड़ताल और ऊंचा आयात शुल्क लगाकर न्यूनतम स्तर पर ला देना। और तीसरा, जो चीजें चीन से हर हाल में मंगानी जरूरी हों, उन्हें किसी और देश को बीच में डालकर मंगाना, जिसे उन्होंने 'चाइना प्लस वन' पॉलिसी का नाम दिया है। इस तीसरी रणनीति का हिस्सा बनकर ही मेक्सिको पिछले दो-तीन वर्षों में अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है।

महाशक्तियों के बीच हथियारों की सीमा संबंधी सभी वार्ताएं खत्म

प्रशांत दीक्षित

एनी जैकबसन की रोमांचक थ्रिलर पुस्तक %परमाणु युद्ध = एक परिदृश्य% परमाणु युद्ध की भयावहता को स्पष्ट करती है कि कैसे दुनिया परमाणु हथियारों से नष्ट हो सकती है। इस पुस्तक को वास्तविक अर्थों में एक क्लासिक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमें दृढ़ता से याद दिलाती है कि हम अपने डाटाबेस से परमाणु प्रलय की काली छाया को खत्म नहीं होने देंगे। इस वर्ष की सिपरी रिपोर्ट से हमें इस भयावह परिदृश्य का एहसास होता है कि हम दुनिया भर में फैले दुश्मनों के बीच 12,121 से ज्यादा परमाणु हथियारों के साथ जी रहे हैं। अनुमान है कि अमेरिका और रूस के पास हर समय क्रमशः 1,770 और 1,710 हथियार तैनात रहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास क्रमशः 120, 280 और 24 हथियार तैयार हैं। संग्रहीत हथियार 5,684 हैं और सैन्य भंडार में 9,585 हथियार हैं।

इस परिदृश्य को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट और भयावह बनाती है, जिसमें बताया गया है कि %रूस सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें जंगी परमाणु हथियारों के उपयोग का अभ्यास किया जाएगा। यह 6 मई, 2024 तक की ताजा रिपोर्ट है। सैन्य अभ्यास में गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए तैयारी और तैनाती का अभ्यास इसमें शामिल होगा। रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में मिसाइल संरचनाएं होंगी और नौसेना बल इसमें भाग लेंगे।

अभ्यास के दौरान, %तथाकथित% गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैयारी और उपयोग के कई उपाय किए जाएंगे। यह जंगी परमाणु हथियारों के लिए एक गलत नाम है। रूस का दावा है कि अभ्यास का उद्देश्य %रूसी संघ के खिलाफ कुछ पश्चिमी अधिकारियों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों और धमकियों के जवाब में% रूस की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित करना है। रूसी सेना की लीक हुई फाइलों के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन की सेनाओं ने एक प्रमुख विश्वशक्ति के साथ संघर्ष के शुरुआती चरण में जंगी परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अभ्यास किया है, जिसमें चीन द्वारा आक्रमण के लिए प्रशिक्षण भी शामिल हैं। रूस अपने परमाणु शस्त्रागार को अपनी रक्षा नीति की आधारशिला मानता

है और कुछ युद्धक्षेत्र में पहले परमाणु हमला करने के लिए यह अपने बलों को प्रशिक्षित करता है।

सैन्य अभ्यासों से पता चलता है कि 'यदि पारंपरिक तरीकों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो परमाणु हथियारों का उपयोग करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।' रूस के जंगी परमाणु हथियार, जिन्हें जमीन या समुद्र से प्रक्षेपित मिसाइलों या विमानों से पहुंचाया जा सकता है, यूरोप और एशिया में सीमित युद्धक्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि बड़े %रणनीतिक% हथियारों का उद्देश्य अमेरिका पर हमला करना है।

रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है और हमें भरोसा दिलाया जाता है कि जंगी परमाणु उपकरण का कोई रणनीतिक मतलब?नहीं होता! हालांकि, अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक जंगी हथियार अब भी 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए हथियारों की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा जारी कर सकते हैं। रूस ने इसी वर्ष जून में उत्तर कोरिया के साथ एक पारस्परिक हथियार आपूर्ति संधि पर भी हस्ताक्षर किए, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने शस्त्रागार को बढ़ाना और जंगी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार भरना है।

अमेरिका भी मानो इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। अप्रैल 2023 में, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने ग्लोबल थंडर नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया था, जिसमें देश की परमाणु कमान, नियंत्रण और संचालन प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण व सत्यापन किया गया। इसकी योजना एक साल पहले से ही बनाई जा रही थी। यह रणनीतिक कमान के जवानों और इकाइयों को मित्र राष्ट्रों और साझेदार संगठनों के साथ प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है, ताकि एकजुटता मजबूत की जा सके और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी अमेरिका के रणनीतिक निवारक बल की तत्परता, प्रभावशीलता और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

नाटो सहयोगियों ने भी अपनी गति बनाए रखी है और उसने 24 जनवरी, 2024 को दशक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें 90,000 जवानों को उत्तरी अटलांटिक और यूरोप में महीनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार किया गया। अभ्यास मुख्य रूप से पोलैंड और नॉर्वे में हो रहे हैं, लेकिन जर्मनी, बाल्टिक राज्यों, रोमानिया, फिनलैंड, स्लोवाकिया, ग्रीस और स्वीडन में भी हो रहे हैं। दावा किया गया कि यह अभ्यास यूक्रेन में रूस के %विशेष सैन्य अभियान% और व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूरोप के पूर्वी देशों को दी गई धमकियों पर प्रतिक्रिया देने की गठबंधन की क्षमता का परीक्षण करेगा। इस तरह से परमाणु टकराव की स्थिति पूरी तरह से तैयार है। इसमें चीन भी पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने अपने शस्त्रागार में 90 और परमाणु हथियार जोड़ लिए हैं और उन्हें हाई अलर्ट पर रखा है। परमाणु हथियारों में इस वृद्धि के कारण स्पष्ट रूप से हैरान करने वाले हैं। दावा किया जाता है कि 11 मार्च, 2024 को अग्नि पांच पर भारत द्वारा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (एमआईआरवी) का परीक्षण चीनी कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि भारतीय अनुसंधान प्रतिष्ठान केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन के उस चुनिंदा समूह में शामिल होना चाहता है, जिनके पास यह क्षमता है। रणनीतिक मजबूरियों की वजह से शायद भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता! ऐसे में, हम इस धारणा से बच नहीं सकते कि हम एक अत्यंत प्रतिकूल शीतयुद्ध परमाणु परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जबकि ध्यान देने वाली बात है कि महाशक्तियों के बीच हथियारों की सीमा संबंधी सभी वार्ताएं खत्म हो गई हैं।

मुंबई की कोर्ट में क्यों आया केजरीवाल केस का जिक्र

अभिनय आकाश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को इस आधार पर रिहा कर दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार किए जाने के कारण के साक्ष्य् उपलब्ध नहीं कराए। दरअसल, आरोपी, व्यवसायी पुरुषोत्तम मंधाना को ईडी ने 19 जुलाई को 975 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।गिरफ्तार किए गए 70 वर्षीय व्यवसायी को दोषी बताने वाले दस्तावेज पेश करने में ईडी फेल रही। विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। कोर्ट ने ईडी ओर से की गई व्यवसायी की हिरासत बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए उसे रिहा करने के लिए कहा।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 में कहा गया है कि गिरफ्तारी करने के लिए एक ईडी अधिकारी को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपना विश्वास करने का कारण दर्ज करना होगा कि आरोपी किसी अपराध का दोषी है। पीएमएलए प्रावधान में ये भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद, जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करें। ये वाक्यांश और उनके सटीक अर्थ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पीएमएलए का कड़ा ढांचा जमानत देना लगभग असंभव बना देता है। फिर, किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानून का ईमानदारी से पालन करते हुए जमानत के लिए उच्च सीमा को उचित ठहराया जाना चाहिए। पीएमएलए की धारा 45 अदालतों को किसी आरोपी को जमानत देने से रोकती है जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है। चूँकि यह किसी अभियुक्त के लिए मुकदमा शुरू होने से पहले ही बेगुनाही साबित करने के लिए एक उच्च बाधा है, इसलिए

गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देना ही अभियुक्त की रिहाई सुनिश्चित करने का एक और कानूनी रास्ता है।

12 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, तो उसने ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति पर बड़ी चिंताएं जताईं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए दलील दी कि ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. अनिवार्य रूप से, इसका मतलब ईडी के विश्वास करने के कारणों को चुनौती देना है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे, और गिरफ्तार किए जाने योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार, मनमाने ढंग से और अधिकारियों की इच्छानुसार गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसे कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हुए वैध %विश्वास करने के कारणों% के आधार पर बनाया जाना है। वास्तव में उचित और आवश्यक होने पर न्यायिक जांच न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत पर लगाए गए संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य का त्याग और विफलता होगी कि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। ईडी ने तर्क दिया कि यह आंतरिक संचार का हिस्सा है और अदालत द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार थी या नहीं। परिणामस्वरूप, यदि किसी आरोपी को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देनी है, तो लिखित रूप में विश्वास करने के कारण प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा। यह दस्तावेज़, अब तक, केवल आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहा है, लेकिन आरोपी के साथ अनिवार्य रूप से साझा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि विश्वास करने के कारण, जैसा कि लिखित रूप में दर्ज किया गया है, प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

2023 में पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य था। एमएलए की धारा 19 में यह आवश्यकता भी शामिल है। हालाँकि यह आवश्यकता केवल प्रक्रियात्मक प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह देखते हुए कि गिरफ्तारी के बाद वास्तव में एजेंसी के लिए जोखिम बढ़ जाता है, स्ष्ट ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार साझा किए जाएं। आमतौर पर, ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति को रिमांड के लिए (उसे पुलिस या न्यायपालिका की औपचारिक हिरासत में भेजने के लिए) मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रियात्मक ढाल को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 तक भी बढ़ा दिया है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि दिल्ली पुलिस उन्हें सूचित करने में विफल रही थी।

ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय उचित प्रक्रिया पर जोर देते हैं और राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। ये फैसले इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वापसी का प्रतीक हैं। इस फैसले ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसकी व्यापक, व्यापक शक्तियों को मजबूत किया।

संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर बहस अनावश्यक

कृष्णमोहन झा

शासकीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए उन पर जो प्रतिबंध लगभग 58 वर्ष पूर्व केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था उसे वर्तमान केन्द्र सरकार ने हटा दिया है। शासकीय कर्मचारी संघ अब संघ की गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि आर एस एस 99 साल से राष्ट्र निर्माण और समाज की सेवा के काम में लगा हुआ है । पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए, आर एस एस जो कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है,की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध को हटाने का वर्तमान केन्द्र सरकार का यह निर्णय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत? करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार के इस निर्णय पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आर एस एस राष्ट्र के पुनर्निर्माण निर्माण का आंदोलन है। संघ अपने लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए जीने वाले कर्मठ, चरित्रवान और देशभक्त कार्यकर्ता तैयार करता है।ये कार्यकर्ता समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि संघ ने शासकीय कर्मचारियों को उसकी गतिविधियों में भाग लेने से रोकने वाला प्रतिबंध हटाने का कोई अनुरोध सरकार से नहीं किया था।यह फैसला केंद्र सरकार ने स्वविवेक से किया है। गौरतलब है कि सन् 2000 में तत्कालीन सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने अथवा न लेने की कार्य वाही में हस्तक्षेप न करते हुए इसके निर्णय का अधिकार सरकारों पर छोड़ दिया था। वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2014 में हरिद्वार में आयोजित एक बैठक में कहा था कि हम सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं करने जा रहे।हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम ऐसे किसी अवरोध से नहीं रुकता। यह बात सही है कि हाल के वर्षों में संघ की किसी भी बैठक में यह मुद्दा विचार के लिए नहीं उठाया गया लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने के लगभग तीन माह पूर्व केंद्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने वाला फैसला लेकर एक स्वागतेय कदम उठाया है। केंद्र सरकार के उक्त निर्णय की उन विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की जा रही है जिनका हमेशा से ही पूर्वाग्रह रहा है। ऐसे विपक्षी दल आखिर यह क्यों भूल जाते हैं कि अतीत में एकाधिक अवसरों पर न्यायालय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर- राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन बता चुके हैं।1967 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शासकीय कर्मचारी को आर एस एस की गतिविधियों में भाग लेने के कारण पद से हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए कहा था कि आर एस एस राजनीतिक संगठन नहीं है अतः उसकी गतिविधियों में भाग लेना गैरकानूनी नहीं है। इसी तरह 1966 में मैसूर हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया आर एस एस गैर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो किसी भी गैर हिन्दू के प्रति द्वेष अथवा घृणा की भावना से मुक्त है।

पढ़ाई को साथ-साथ काम करना चाहते है तो यह देश है बेस्ट

बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करें। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत सारे लोग अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आज कल के बढ़ते पार्ट टाइम वर्क कल्चर को देखते हुए अब विदेश जाकर पढ़ना आसान हो गया है। कई स्टूडेंट्स क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करते है। जिससे उनकी छोटी-मोटी जरूरतों का खर्च निकाला जा सके। भारत में भी यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन विदेशों में कई ऐसे यूनिवर्सिटी और संस्थान है जहां आप पढ़ते है वहीं संस्थान आपको पार्ट टाइम नौकरी की ऑफर देने लगे है। यूएस या दूसरें विकसित देशों में अर्न व्हाइल यू लर्न का केवल चलन ही नहीं हा बल्कि वहां के लोग इसे अहमियत भी देते हैं। अर्न व्हाइल यू लर्न का फायदा सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं हो रहा, इससे सीमित अवधि के लिए रोजगार देने वाले भी दोहरा लाभ कमा रहे हैं। यह ट्रेंड उन छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है, जो पढने के लिए विदेश का रुख करते हैं। इन देशों में अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट

फ्रांस

यहां अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को काम करने की इजाजत है, मगर शर्त यह है कि उनका संस्थान नेशनल स्टूडेंट हेल्थकेयर प्लान में शिरकत करता हो। फ्रेंच कानून के तहत स्टूडेंट्स को साल में 964 घंटे काम करने की छूट है।

जर्मनी

अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स, जो ईयू या ईईए देशों के बाहर के छात्र हैं, उन्हें साल में 120 फुल या 240 हाफ डे काम करने का मौका मिल जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स यहां निर्धारित काम के घंटों से अधिक काम करना चाहता है तो उसके लिए उसे संबंधित डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होती है। साथ ही यदि छात्र का कोर्स व कार्य की प्रकृति एक ही है तो उसे काम के असीमित घंटे मिलते हैं।

न्यूजीलैंड

यहां वेरिएशन ऑफ कंडीशन के तहत पढ़ाई करते हुए 20 घंटे प्रति सप्ताह तक काम करने की आजादी होती है, मगर उसके लिए उनकी कुछ शर्तों को मानना पड़ता है।

कनाडा

यहां अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कैम्पस में काम करने की पूरी छूट है, मगर ऑफ कैम्पस के लिए वर्क परमिट प्रोग्राम के अनुसार ही चलना पड़ता है। नियमित सैशन के दौरान जहां 20 घंटे प्रति सप्ताह काम किया जा सकता है, वहीं विंटर और समर ब्रेक के दौरान फुल टाइम काम करने की इजाजत होती है।

सिंगापुर

यहां अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के साथ या छुट्टियों में काम की इजाजत नहीं होती, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन मैनपावर विभाग से वर्क पास की अनुमति ली जा सकती है। हालांकि कुछ स्कूल्स में 14 वर्ष से बड़े छात्रों को काम करने की छूट है।

यूनाइटेड किंगडम

बैचलर डिग्री और उससे ऊपर के छात्रों को प्रति सप्ताह 20 घंटे काम करने की इजाजत है। इसके अलावा छुट्टियों के दौरान फुलटाइम वर्क किया जा सकता है। वहीं बैचलर डिग्री से नीचे के छात्रों को सिर्फ 10 घंटे प्रति सप्ताह काम करने की इजाजत मिलती है।

आयरलैंड

ऐसे अंतरराष्ट्रीय छात्र, जो ईईए देशों से बाहर के हैं और जो यहां किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम एक साल का पूर्णकालिक कोर्स कर रहे हैं, वे 20 घंटे प्रति सप्ताह तक का पार्ट टाइम रोजगार पा सकते हैं।

इटली

अगर किसी अंतरराष्ट्रीय छात्र के पास स्टडी वीजा है और इटली में रहते हुए उसे 90 दिन से अधिक हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में वह रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। रेजिडेंस परमिट के बाद वह 20 घंटे प्रति सप्ताह की पार्ट टाइम जॉब कर सकता है।

स्विट्जरलैंड

यहां ईयू/ईएफटीए देशों से बाहर के अतरंराष्ट्रीय छात्रों के लिए 15 घंटे प्रति सप्ताह का रोजगार पाने की इजाजत है। पर यह जरूरी है कि उन्हें यहां रहते हुए कम से कम छह माह का न्यूनतम समय हो चुका हो। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है।

यूनाइटेड स्टेट्स

अंतरराष्ट्रीय छात्र, जिन के पास एफ - 1 वीजा है, उन्हें ऑफ कैम्पस जॉब करने की इजाजत नहीं है। किसी खास केस में ही यह इजाजत मिलती है। एक साल के बाद यूएससीआईएस से काम करने की इजाजत मिल सकती है। यहां सिर्फ कैम्पस में 20 घंटे प्रति सप्ताह सैशन के समय और 40 घंटे प्रति सप्ताह छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए इजाजत नहीं लेनी होती।

आस्ट्रेलिया

छात्रों को यहां अधिकतम 40 घंटे प्रति पखवाड़े तक काम करने से नहीं रोका जाता। वहीं छुट्टियों में काम करने के घंटों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

आज कल के बढ़ते पार्ट टाइम वर्क कल्चर को देखते हुए अब विदेश जाकर पढ़ना आसान हो गया है। कई स्टूडेंट्स क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब करना पसंद करते है। जिससे उनकी छोटी-मोटी जरूरतों का खर्च निकाला जा सके। भारत में भी यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन विदेशों में कई ऐसे यूनिवर्सिटी और संस्थान है जहां आप पढ़ते है वहीं संस्थान आपको पार्ट टाइम नौकरी की ऑफर देने लगे है।

कुछ यूं बनाएं अपनी वेबसाइट

आजकल पर्सनल वेबसाइट बनाने का प्रचलन भी जोरों पर है। वेबसाइट आपको अवसर देती है अपने बारे में तमाम तरह की सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की। घर बैठे आपके बारे में तमाम सूचनाओं को एक्सेस करने की आजादी का इससे बेहतर जरिया और भला क्या हो सकता है। हालांकि इस काम के लिए ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आदि का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी आज के इस तकनीकी युग में पर्सनल वेबसाइट होना आपको दूसरों से अलग बनाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेबसाइट बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा। इंटरनेट पर कई ऐसे टूल्स हैं, जिनकी सहायता से चुटकियों में आप अपना वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। क्या हुआ यदि आपको कंप्यूटर में महारथ हासिल नहीं है, प्रोग्रामिंग के आप पंडित नहीं हैं या फिर कोडिंग के नाम से ही आप डरने लगते हैं। प्रोफेशनल्स, रिसचर्स, स्टूडेंट्स आदि अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। इसके माध्यम से आप न केवल वर्चुअल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, बल्कि अब तो एडवरटाइडिंग के जरिए पैसा कमाने का भी यह एक सोर्स बन गया है।

वेबसाइट आमतौर पर दो तरह की होती है- स्टैटिक और डायनॉमिक। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब वैसी साइट से है, जो वन-वे होती है। यहां आप वेब पेजों को केवल पढ़ कर जानकारी ले सकते हैं। ये साइट्स नॉन-इंटरेक्टिव होती हैं और ये केवल स्टैटिक इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराती हैं, जो प्री-डिफाइन होती है। वैसे वेब पेज को एचटीएमएल (हाइपर टैक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) की सहायता से तैयार किया जाता है। इसके विपरीत डायनॉमिक वेबसाइट इंटरेक्टिव होती है और विभिन्न क्राइटेरिया के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यहां आपको डाटाबेस से डायनामिक कंटेंट्स मिलता है और आप ताजा-तरीन (लेटेस्ट) इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया में आपको डोमेन नेम/सब-डोमेन नेम और वेबसाइट होस्टिंग साइट की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम सिस्टम के आधार पर डोमेन नेम बनाया जाता है। इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो निःशुल्क सब-डोमेन प्रोवाइड करती हैं। आप गूगल सर्च की सहायता ले सकते हैं। www.hosting.com एक ऐसी ही वेबसाइट है, जहां आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इस दौरान आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड, ई-मेल एड्रेस आदि एंटर करना पड़ेगा। किसी भी वेबसाइट होस्टिंग साइट का उपयोग करने से पहले उसके फीचर्स, क्राइटेरिया आदि को सही से समझ लें। डोमेन और यूआरएल के बारे में निर्णय कर लेने के बाद जो मुख्य काम है, वह है वेबसाइट का निर्माण। यहां आप विभिन्न वेब पेज डेवलप करते हैं, जो वेबसाइट का रूप लेते हैं। नेट पर विभिन्न वेब एडिटर्स हैं, जहां आप बिना कोडिंग किए ही आकर्षक और प्रोफेशनल वेब पेज बना सकते हैं। इन एडिटर्स में आपको संबंधित इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इन एडिटर्स की सहायता से वेबसाइट डेवलप करते समय आप कलर, फोंट, स्टाइल, बैकग्राउंड, इमेज आदि पर विशेष ध्यान रखें, ताकि आपकी वेबसाइट आकर्षक दिखे। फ्रंट पेज यानी होम पेज को डिजाइन करते समय खास ध्यान दें। नेविगेशन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, आप याद रखें किसी भी साइट का कंटेंट उस साइट की सफलता और लोकप्रियता में मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसे में कंटेंट को दूसरों के लिए रोचक और उपयोगी बनाएं, ताकि लोग आपकी साइट के प्रति आकर्षित हों। वेबसाइट तैयार हो जाने पर अगला कदम होता है पब्लिशिंग यानी इंटरनेट पर इसे अपलोड करना। चुनी गई होस्टिंग साइट पर आप पर्सनल वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) द्वारा अपनी वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं, ताकि जब भी सर्च इंजन में संबंधित सर्च किया जाए तो आपकी वेबसाइट भी सर्च लिस्ट में प्रदर्शित हो।

तेजी से पंख फैलाते इंटरनेट का सहारा लेकर आज हर व्यक्ति अपनी पहुंच इंटरनेट की दुनिया में दर्ज कराने को बेताब नजर आता है। हर व्यक्ति की यही चाहत है कि उसका दायरा किसी सीमा के बंधन में कैद न रहे। सच ही तो है, आज नेट ने हमें भौगोलिक सीमाओं को लांघने का एक बेहतर जरिया उपलब्ध कराया है और साथ ही दी है वर्चुअल वर्ल्ड में उन्मुक्त विचरने की आजादी।

अपनाएं यह 5 तरीके जल्द मिलेगी नौकरी

जॉब मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जॉब मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो गया है लेकिन अभी भी उन उम्मीदवारों को कहीं न कहीं बेहतर जॉब जरूर मिल जाती है जो योग्य होते हैं। लेकिन इतना जरुर है कि समय के साथ- साथ जॉब सर्च करने, टेस्ट और इंटरव्यू देने के तरीके भी बदल गए है। इसलिए इन बातों को जानना बहुत जरुरी है।

ऑनलाइन नेटवर्किंग

जॉब सर्च करने के लिए आप फेसबुक, लिंकडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको थोड़ी होशियारी बरतनी होगी। अगर आप हमेशा दूसरों से खुद के बारे में बात करेंगे तो धीरे-धीरे लोग आपके प्रोफाइल पर ध्यान देना बंद करेंगे। ऑनलाइन नेटवर्किंग एक कॉकटेल की तरह है इसलिए इसका अपने फायदे में ध्यान से इस्तेमाल करें।

पर्सनल नेटवर्किंग

बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को गलत मानते हैं मगर ऐसा नहीं है। लोगों से खुल कर बातें करें, अपने लक्ष्य तय करें। दूसरों से मिलने-जुलने के कारण आपके स्किल्स में सुधार भी आएंगे और समय आने पर मदद भी मिलेगी। नौकरी तलाशने में नेटवर्किंग का काफी अहम रोल होता है।

खुद को थोड़ा अलग रखें

जब आप जॉब के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि पुरानी घिसी-पिटी बातें जो सभी के रिज्यूमे में होती है, उसको फॉलो न करें। आप अपने रिज्यूमे में कुछ ऐसी बातें डालने की कोशिश करें जो आपको दूसरों से अलग बनाएं।

इंटरव्यू इंफॉर्मेशन

जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो सिर्फ सवालों के जवाब न दें बल्कि अपनी आवश्यकतानुसार कुछ सवाल आप भी पूछ लें। जैसे कि इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? वे क्या करते हैं? इंटरव्यू देकर निकलें तो धन्यवाद कहना न भूलें।

इंटरव्यू में सीधी बात करें

इंटरव्यू में घुमावदार जवाब देने से बचें। सवालों का सीधा जवाब दें। अगर आपसे आपकी कमजोरी के बारे में पूछा जाए तो अपनी कमजोरी ही बताएं। कुछ लोग अपने को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वे ज्यादा काम करने को अपनी कमजोरी बताने लगते हैं इसलिए ऐसे सवालों की तैयारी पहले से करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केजरीवाल, सिसोदिया और कविता को नहीं मिली राहत

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस विधायक के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट का आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई; 9 अगस्त तक) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी; 13 अगस्त तक) दोनों द्वारा की जा रही जांच पर लागू होता है। जबकि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसौदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की कविता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता द्वारा दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में हैं। सीबीआई, केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई मामले के कारण वह हिरासत में हैं।

राहुल, प्रियंका का वायनाड का प्रस्तावित दौरा स्थगित

नईदिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने प्रतिकूल मौसम के चलते वायनाड का अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया है। दोनों बुधवार सुबह वायनाड रवाना होने वाले थे। राहुल गांधी ने मंगलवार रात 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''प्रियंका और मैं भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए कल वायनाड जाने वाले थे। हालाँकि, लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि विमान उतर नहीं सकेगा।'' उन्होंने कहा, ''मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द दौरा करेंगे। इस बीच, हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं वायनाड के लोगों के साथ हैं।'' वायनाड जिले में मेप्पडी के पास भारी बारिश के कारण विभिन्न पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भूस्खलन हुआ। इसमें 123 लोगों की मौत की खबर है।

लक्ष्मण प्रसाद ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली

इम्फाल। मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 31 जुलाई को इम्फाल के राजभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ ली। नवनियुक्त राज्यपाल को शपथ मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने दिलाई। आचार्य 30 जुलाई को इंफाल पहुंचे जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष सत्यब्रत सिंह, विभिन्न मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव डॉ विनीत जोशी, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, डीजीपी राजीव सिंह और राजभवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पहले 30 जुलाई को मंगलवार दोपहर गुवाहाटी में असम के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने बुधवार को सिक्किम के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार ला रही नया कानून

नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। इसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

नईदिल्ली। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बचाव करते हुए कहा कि उनकी जाति संबंधी टिप्पणी किसी व्यक्ति को लक्षित नहीं थी क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था तो फिर इसे अपने ऊपर कौन ले रहा है? इंडी गठबंधन में बेहद असमंजस की स्थिति है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि संसद में राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था और कहा था कि कांग्रेस जाति में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने इसे ब्रिटिश काल का सांप्रदायिक पुरस्कार भी बताया। एक नारा हुआ करता था, जात पर, न पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। राहुल गांधी इसे क्या लेकर आए? उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि आज पुरखों की बात को रख के लात पे, पार्टी को ले आए फुटपाथ पर...।

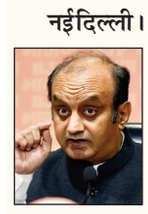

अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष का हंगामा, माफी की मांग की, भाजपा ने किया बचाव

नईदिल्ली। मंगलवार को लोकसभा में जाति जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण के बाद विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि कांग्रेस ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। ठाकुर की टिप्पणी पर बुधवार को संसद में हंगामा हुआ। जहां अनुराग ठाकुर के भाषण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ठाकुर पर हमला करते हुए पूछा कि वे किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं।

विपक्षी दलों के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी.चिदंबरम ने कहा कि इस दिन और युग में, अगर किसी को इतनी प्राचीन चीज़ के बारे में प्रश्न पूछने की ज़रूरत है तो यह अप्रिय है। मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह के असभ्य व्यवहार का हमारे सार्वजनिक संवाद में कोई स्थान नहीं है। सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बदतमीज़ है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और पीएम उनका समर्थन करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी।

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि यह ठाकुर जी का स्वभाव है। आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। अगर वह इस स्तर तक गिर कर बोल सकते हैं...तो इसका मतलब है कि आपकी नींव कमजोर है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश को जरूरत है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारी जाति है देश की सेवा करना और धर्म है भारत माता को आगे ले जाना। ये वे लोग हैं जो देश को इस तरह से ढालना चाहते हैं जो उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो...उन्होंने जो कहा वह निंदनीय है, मुझे उम्मीद है कि उनके नेता उनसे माफी मांगेंगे।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि यह बीजेपी के अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा अलग तरीके से सोचते हैं। उनकी एक पदानुक्रमित मानसिकता है। राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि राहुल गांधी हर उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो उत्पीड़ित है, आवाजहीन है। राहुल गांधी का जवाब बेहद सौम्य, सच्चा और शालीन था. उन्होंने जवाब दिया कि आप सदन में जितनी शर्तों पर अपमान करना चाहें कर सकते हैं लेकिन मैं सामाजिक न्याय के लिए खड़ा रहूंगा और हम सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के लिए काम करेंगे। अगली कार्रवाई के रूप में, मैंने संसद में स्थगन प्रस्ताव नोटिस पेश किया है क्योंकि जनगणना में देरी हुई है।

लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो लोग जाति नहीं जानते वे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने सदन में इसे स्पष्ट किया। उन्हें कोई बहाना चाहिए. इरादा मुद्दे को भटकाने का है. पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक - सभी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने जो किया उसकी मैं निंदा करता हूं, वो हर वक्त जातियों की बात करते रहते हैं... वो मीडिया वालों और सेना के जवानों की जाति पूछते हैं... कांग्रेस ने देश को जातियों के आधार पर बांटने की साजिश रची है... वो जाति पूछते रहते हैं सबकी जातियां, लेकिन राहुल गांधी की जाति नहीं पूछी जा सकती...क्या वे देश और संसद से ऊपर हैं?...वे लोकतंत्र और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं, अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं।

माहौल हमारे पक्ष में, इसे बरकरार रखने की जरूरत : सोनिया गांधी

नईदिल्ली। प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव आने से पहले कांग्रेस संसदीय दल की आज बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि माहौल हमारे पार्टी के पक्ष में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो गति और सद्भावना पैदा हुई थी, उसे बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यदि हम लोकसभा चुनावों में देखे गए रुझान को दर्शाते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आएगा।

गांधी ने मोदी सरकार पर लोकसभा चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण गिरावट से सही सबक नहीं लेने और समुदायों को विभाजित करने और भय और दुश्मनी का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम रहने का भी आरोप लगाया। 77

वर्षीय ने पहली बार सांसदों के लिए एक विशेष संदेश भी दिया, जिसमें उनसे पूरी तरह से तैयार रहने, संसद सत्र न चूकने और समिति के कार्यों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप में से कई लोग पहली बार सांसद बने हैं। कल हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ऐसे और भी मौके आएंगे। मैं बस यह दोहराना चाहती हूं कि हममें से प्रत्येक को पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें नियमित रूप से संसद में उपस्थित रहना चाहिए, हर समय सतर्क रहना चाहिए और अपनी समिति के कार्यों को गंभीरता से लेना चाहिए।

पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि कांग्रेस संसदीय दल को अधिक व्यापक शोध समर्थन और बैकअप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास एक प्रणाली है, लेकिन हमारी बढ़ती संख्या के साथ, इस प्रणाली को जल्द ही मजबूत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं से लोकसभा चुनाव में उत्पन्न हुई गति और सद्भावना को बनाए रखने और उद्देश्य की भावना के साथ एकजुट होकर काम करने का भी आग्रह किया।

बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने हफ्तों तक हुई भारी बारिश के कारण हुए वायनाड भूस्खलन का जिक्र किया, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने झारखंड में मुंबई-हावड़ा मेल के पटरी से उतरने के बाद कुप्रबंधन के कारण हुई रेलवे दुर्घटनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें दो की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। 77 वर्षीय ने राष्ट्रीय जनगणना कराने में देरी को लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की, जो 2021 से होनी है।

वायनाड भूस्खलन: 23 जुलाई को दी गई थी समय पूर्व चेतावनी: शाह

नईदिल्ली। वायनाड भूस्खलन मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि मैं देश के लिए कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। वे पूर्व चेतावनी की बात करते रहे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को, भारत सरकार ने केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी, जो घटना से 7 दिन पहले थी, और फिर 24 और 25 जुलाई को भी पूर्व चेतावनी दी गई थी। 26 जुलाई को चेतावनी दी गई थी कि 20 सेमी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है और भूस्खलन की भी संभावना है, कीचड़ हो सकता है और इसमें लोगों की जान भी जा सकती है।

शाह ने कहा कि जो लोग सरकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए 2014 के बाद 2000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की चेतावनी का उपयोग करके शून्य हताहत आपदा प्रबंधन किया है।

ओडिशा में जब नवीन बाबू की सरकार थी, तो हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी गलती से। गुजरात सरकार को हमने 3 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, एक पशु भी नहीं मरा।

उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि केरल सरकार ने क्या किया? वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, कौन रोक रहा था। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2023 तक दुनिया का सबसे आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली भारत में है। इसमें 7 दिन पहले अनुमान देने वाले दुनिया में 4 ही देश हैं, जिनमें से एक भारत है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस मामले पर टिप्पणी करने से बचूंगा, लेकिन चूंकि भारत सरकार की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर सवाल उठाया गया है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी बात सुनें, चिल्लाने से बचें और इसके बजाय, जारी की गई चेतावनियों को पढ़ें। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश

पीवी सिंधु पेरिस 2024 ओलंपिक के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। उन्होंने बुधवार को पोर्टे डे ला चैपल एरिना में अपने अंतिम ग्रुप-स्टेज मैच में एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा को हराकर अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। सिंधु का राउंड 16 में चीन की ही बिंग जियाओ से मुकाबला होगा।

अपने दूसरे और अंतिम ग्रुप-स्टेज मैच में सिंधु ने कुबा को 21-5, 21-10 के स्कोर से हराया। इससे पहले, उन्होंने अपने पहले मैच में मालदीव की फतिमाथ नबाहा अब्दुल रज्जाक को 21-9, 21-6 से आसानी से हराया था।

सिंधु की जीत का मतलब है कि वह नॉकआउट स्टेज में आगे बढ़ने वाली सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी में शामिल हो गई हैं। पूर्व विश्व चैंपियन अब गुरुवार को राउंड ऑफ 16 में चीन की ही बिंग जियाओ से भिड़ेंगी, जो ग्रुप एन में टॉप पर रही थीं।

लक्ष्य सेन ने रच दिया इतिहास

लक्ष्य सेन ने पुरुष बैडमिंटन में बड़ा धमाका करते हुए रास्ते का रोड़ा हटा दिया है। उन्होंने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को पराजित करते हुए मुकाबला जीत लिया और नॉक आउट में जगह हासिल की। लक्ष्य सेन ने सीधे सेटों में अपना मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया।

पहले हाफ में जोनाथन क्रिस्टी और लक्ष्य सेन ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। ब्रेक तक मामला लगभग बराबरी का ही था। इसके बड़ा जोनाथन ने ने तेजी दिखाते हुए लक्ष्य से आगे निकलने में सफल रहे। लक्ष्य ने वापसी करते हुए सेट पॉइंट तक चले गए और 21-18 से सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में ब्रेक के बाद लक्ष्य ने अपनी रफ्तार जारी रखी और जोनाथन को कोई मौका नहीं देते हुए लगातार लीड बनाये रखी उन्होंने 21-12 से मुकाबला जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली। पहली बार खेलते हुए ओलंपिक में उन्होंने धमाका कर दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 286 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,951 के ऑलटाइम हाई पर

नईदिल्ली। मेटल, बिजली और चुनिंदा ऑटो शेयरों में बढ़त के कारण भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स लगभग 286 अंक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बुधवार को 24,950 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 285.94 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 81,741.34 के ऑलटाइम क्लोजिंग हाई पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में इंडेक्स बढ़त के साथ खुला और 372.64 अंक या 0.45 प्रतिशत उछलकर इंट्रा-डे के उच्चतम स्तर 81,828.04 पर पहुंच गया। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 93.85 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़कर 24,951.15 के ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 127.3 अंक या 0.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का 31 जुलाई को आखिरी दिन था। रात 12 बजे से पहले आईटीआर फाइल नहीं करने पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो 1 अगस्त से नई कर व्यवस्था आपके लिए डिफॉल्ट मानी जाएगी। यहां तक कि अगर आप 31, 2024 दिसंबर तक विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, तो भी कर गणना के लिए आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम सिंघल के अनुसार यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आपके पास 31 दिसंबर तक इसे फाइल करने का विकल्प हैं लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

जीडीपी का बड़ा हिस्सा बनेगी डिजिटल इकोनॉमी

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और 2026 तक यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 'वित्तवर्ष 2023-24 के लिए धन और वित्त रिपोर्ट' में उल्लेख किया कि वित्तीय उद्योग में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से लोगों को अधिक बैंकिंग विकल्प मिल रहे हैं और वित्तीय सेवाएं सभी के लिए अधिक सुलभ और लागत प्रभावी हो रही हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 10% है, 2026 तक दोगुनी होकर 20% हो जाएगी, जिसका कारण वृद्धि के रुझान और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि और कम डेटा लागत जैसे कारक हैं। भारत में मोबाइल डेटा का उपयोग बहुत अधिक है, 2023 में प्रति व्यक्ति औसतन 24.1 जीबी है।

स्कॉर्पियो बनाने वाली कंपनी का 23% बढ़ा नेट प्रॉफिट

नईदिल्ली। भारत में स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700 और थार जैसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ने वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही के परिणाम घोषित कर दिए हैं। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसका स्टेंडअलोन नेट प्रॉफिट 23 फीसदी बढ़कर 2,613 करोड़ रुपये हो गया। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 2,120 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, तिमाही आधार पर कंपनी के नेट मुनाफे में 5 फीसदी की कमी आई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करते समय बताया कि उसका रेवेन्यू 11% बढ़कर 27,133 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 24,403 करोड़ रुपये था। इंडस्ट्री की तरफ से दिए गए डेटा के मुताबिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा की कारों की बिक्री सबसे ज्यादा हुई।

युवा आबादी में देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की क्षमता

पत्रलेखा चटर्जी

यह कोई रहस्य नहीं है कि भारत की युवा आबादी में देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की क्षमता है। 65 फीसदी से ज्यादा भारतीय 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। भारतीयों की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इस संभावित गतिशील, युवा कार्यबल को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है- कौशल का अंतर, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों से अपेक्षित कौशल और कर्मचारियों के पास वास्तव में मौजूद कौशल के बीच की असमानता को बताता है।

भारत के लाखों युवक-युवतियों के पास, जिनमें औपचारिक डिग्रीधारी भी शामिल हैं, देश में या उसके बाहर आज के गतिशील कार्यस्थल के लायक जरूरी कौशल का अभाव है, चाहे वह विनिर्माण का क्षेत्र हो या सेवा का। भारत की?उन्नति तभी होगी, जब उसका कार्यबल तेजी से बदलते कामकाज की दुनिया में कार्य करने के लिए तैयार हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा तेजी से भविष्य के मुख्य कौशल बनते जा रहे हैं। इसके अलावा, विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता, संकट प्रबंधन और टीम के साथ मिलकर काम करने का हुनर भी महत्वपूर्ण है।

बेशक कुछ सम्मानजनक अपवाद हैं, लेकिन अब भी भारत की शिक्षा प्रणाली व्यापक स्तर पर रटने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है, जिससे युवा लोग कार्य की बदलती दुनिया के लिए अयोग्य साबित होते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है, और इसके लिए व्यापक तौर पर फिर से प्रतिभा को तराशने और पुनर्कौशल की जरूरत है। यह सब नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय बजट-2024 में

प्रस्तावित नई इंटर्नशिप योजना के लिए प्रासंगिक हैं। कौशल पर ऐसे समय में जोर दिया गया है, जब 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कॉलेज से निकलने वाले दो में से लगभग एक स्नातक रोजगार के योग्य नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि, %अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 51.25 फीसदी युवा ही रोजगार के योग्य माने जाते हैं। यानी कॉलेज से निकलने वाले लगभग दो में से एक युवा अभी रोजगार के लिए तैयार नहीं माने जाते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले दशक में यह आंकड़ा 34 फीसदी था, जो बढ़कर 51.3 फीसदी हो गया है।% सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि?2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है।

बजट में प्रस्तावित इंटर्नशिप योजना को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। इस योजना का लक्ष्य 500 शीर्ष भारतीय कंपनियों के माध्यम से पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है। इसका लक्ष्य 21 से 24 वर्ष के वैसे युवा हैं, जो न तो कहीं नौकरी करते हैं और न ही जिन्होंने पूर्णकालिक शिक्षा हासिल की है। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और चार्टर्ड एकाउंटेंसी कॉलेज के स्नातक इसके योग्य नहीं हैं। अधिकांश लागत सरकार खुद वहनकरेगी, लेकिन संगठनों को अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) फंड से इसमें योगदान देना जरूरी है। इस योजना पर नजर डालने से पता चलता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से प्रत्येक को पांच वर्ष में 20,000 युवाओं को इंटर्नशिप कराना होगा, यानी हर साल 4,000 युवाओं को। प्रशिक्षुओं को प्रति माह 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देनी होगी। कंपनियों से अपेक्षा है कि वे अपने सीएसआर फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 फीसदी वहन करें।

यकीनन यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और योजना के बारे में जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। सरकार ने इस पर जोर दिया है कि यह योजना %स्वैच्छिक% है, जिसका मतलब है कि किसी भी कंपनी को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित योजना में किन 500 कंपनियों का संदर्भ दिया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.